

## वैदेशिक क्षेत्र

वर्ष 2016-17 में भारत के वैदेशिक क्षेत्र में बदलाव देखा गया जब लगातार दो वर्ष तक नकारात्मक रहने के बाद निर्यात वृद्धि सकारात्मक हो गई, आयात वृद्धि भी लगातार चार वर्ष तक नकारात्मक रहने के बाद मामूली सी सकारात्मक वृद्धि में रूपांतरित हो गई। इन बातों के चलते, व्यापार घाटे में 1.2 प्रतिशतांक की कमी हुई और वह जीडीपी के 5 प्रतिशत के स्तर पर जा पहुंचा तथा चालू खाता घाटे में 0.4 प्रतिशतांक की गिरावट हुई जिसके चलते वह जीडीपी का 0.7 प्रतिशत रह गया। इन घटनाक्रमों के साथ-साथ सकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में 18.2 प्रतिशत की ज़बरदस्त वृद्धि, विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी और एफसीएनआर(बी) जमाराशियों के अबाध एवं सफल मोचन के बाद विदेशी ऋण में हुई 2.7 प्रतिशत की कमी के परिणामस्वरूप वैदेशिक क्षेत्र की अधिक स्थिर तस्वीर उभरी है। इस वर्ष बड़े नीतिगत परिवर्तन भी देखे गए जैसेकि निर्यात संवर्धन स्कीमों को युक्तिसंगत बनाया गया, निर्यात अवसरंचना निर्मित करने पर नए सिरे से बल दिया गया और व्यापार करना आसान बनाने के उपाय किए गए, विदेशी निवेश की परिधि को और बढ़ाया गया और सबसे महत्वपूर्ण तो यह रहा कि 1 जुलाई, 2017 से लागू किए गए माल और सेवा कर के ब्लूप्रिंट को अंतिम रूप दिया गया।

### वैश्विक आर्थिक माहौल

6.1 वर्ष 2016 में मंदी और वैश्विक व्यापार में गिरावट आने, कमजोर निवेश, चीन में मंदी और बहुत अधिक नीति की अनिश्चितता से विश्व में आर्थिक क्रियाकलाप में गिरावट के कारण वैश्विक वृद्धि 2015 में 3.4 प्रतिशत से गिरकर 2016 में 3.2 प्रतिशत पर आ गयी (अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष का वैश्विक आर्थिक परिदृश्य, जुलाई 2017 अध्ययन) 2016 में धीमा प्रदर्शन के बाद, आर्थिक क्रियाकलाप के 2017 और 2018 में तेज होने का पूर्वानुमान है। इस अवधि में निवेश, विनिर्माण और व्यापार में दीर्घ प्रतीक्षित आवर्ती सुधार आने की संभावना है। वैश्विक वृद्धि 2017 में 3.5 प्रतिशत से बढ़कर 2018 में 3.6 प्रतिशत होने का पूर्वानुमान है, जबकि अधिकांश उन्नत देशों का विकास 2017 और 2018 में तेजी से होने का पूर्वानुमान है, उभरते बाजार और विकासशील देशों के विकास की गति में बहुत अधिक भिन्नता बनी रहेगी। वर्ष 2016 में 6.7 प्रतिशत पर चीन का विकास आशा से

कुछ अधिक है। इसे उत्प्रेरक की सहायता मिलती रही और 2017 में 6.7 प्रतिशत होने का पूर्वानुमान है। 2018 में कुछ धीमा होकर 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। 2016 में भारत की विकास दर 7.1 प्रतिशत रही, जो विश्व के प्रमुख देशों में सबसे अधिक रही और 2017 में इसके 7.2 प्रतिशत पर तथा 2018 में 7.7 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है।

6.2 विश्व व्यापार मूल्य वृद्धि, जो 2015 में एकाएक 13.2 प्रतिशत तक गिरी, 2016 में यद्यपि कम पर 3.2 प्रतिशत गिरना जारी रहा (विश्व व्यापार संघ आंकड़ाधार)। यह वैश्विक विकास और निवेश में गिरावट, संरक्षणवाद में बढ़ोतरी, वस्तुओं की कीमतें गिरने और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में गिरावट के कारण हुआ। विश्व व्यापार की मात्रा (वस्तु और सेवा) विकास भी जो 2015 में 2.6 प्रतिशत था, गिरावट जारी रहने के कारण 2016 में 2.3 प्रतिशत पर आ गया (आईएमएफ डब्ल्यूईओ आंकड़ाधार जुलाई, 2017)। इसके 2017 में 4.0 प्रतिशत और 2018

में 3.9 प्रतिशत पर तेज होने का पूर्वानुमान है (सारणी 1) तथापि, सुधार की गति पहले की आशा से कम है क्योंकि प्रमुख उन्नत देशों में विकास संभावनाओं में कमी, वैश्विक निवेश में आई लगातार नरमी और संयुक्त राज्य

और यूरोप में व्यापार नीति के बारे में अनिश्चितता के साथ ही साथ धीमी या रूका हुआ व्यापार उदारीकरण तथा व्यापार विरोधी एवं संरक्षणवादी उपायों में वृद्धि हुई (बॉक्स 1 देखें)

### सारणी 1. विश्व व्यापार ( वस्तु और सेवा ) का सिंहवलोकन

	अनुमान	पूर्वानुमान		डब्ल्यू ई ओ अप्रैल 2017 के पूर्वानुमान से अन्तर	
	2016	2017	2018	2017	2018
विश्व व्यापार की मात्रा (वस्तु और सेवा)	2.3	4.0	3.9	0.2	0.0
उन्नत देश	2.3	3.9	3.5	0.2	-0.1
ई एम डी ई	2.2	4.1	4.6	0.1	0.3

स्रोत: अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वैश्विक आर्थिक परिदृश्य अध्ययन जुलाई 2017

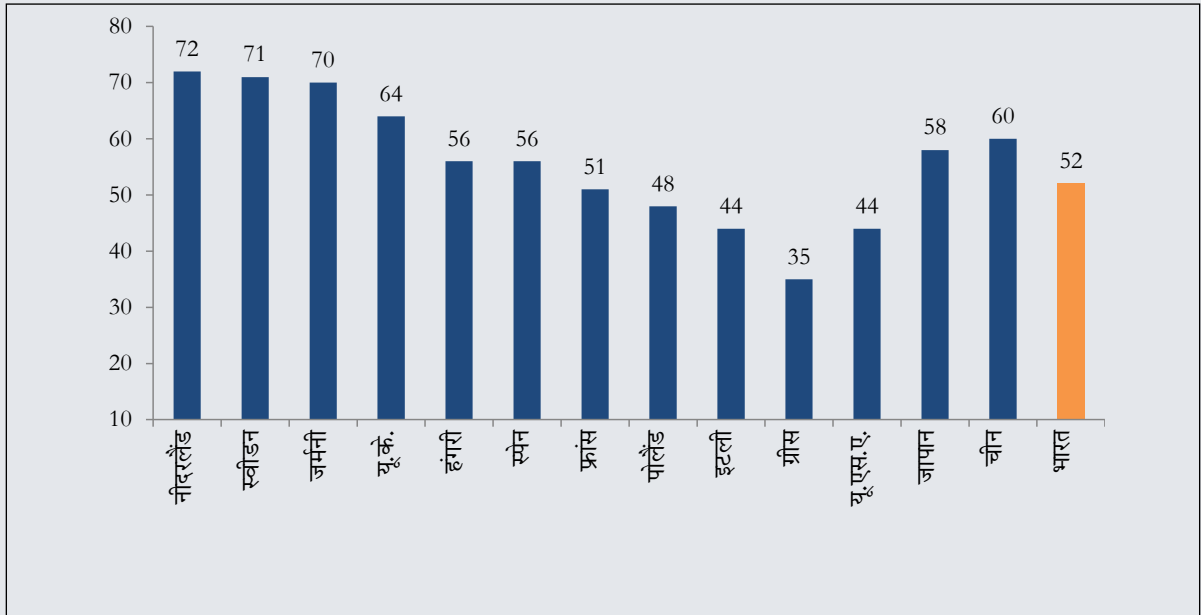
### बॉक्स 1. वैश्वीकरण विरोधी और व्यापार प्रतिबंधात्मक उपाय

**बढ़ता वैश्वीकरण विरोध:** हालिया वर्षों में, चुनाव के दौरान और उसके बाद संयुक्त राज्य में हाल के घटनाक्रम से वैश्वीकरण विरोधी प्रवृत्तियां देखी गई हैं और व्यापार, आप्रवासन और बहुपक्षीय अभिनियोजन पर कुछ संशयवादी दृष्टिकोण रखने वाले लोगों के जनमत के कारण वैश्वीकरण के फायदे के प्रति संदेह हो रहा है। इसके अतिरिक्त अध्ययन से पता चलता है कि 1990 से वैश्विक असमानता में कमी आने के बावजूद बहुत से देशों में असमानता बढ़ी है, विशेषकर उन्नत देशों में। इसी प्रकार आईएमएफ वैश्विक आर्थिक परिदृश्य (अप्रैल 2017) में कहा गया है कि उन्नत देशों में अनेक मध्यम कौशल रोजगार समाप्त हो गए हैं, यह 1990 के प्रारंभिक समय से प्रौद्योगिकीय परिवर्तन का परिणाम है और आय का वितरण उच्चतम अर्जकों के पक्ष में बना रहा और कम आय वालों के लिए आगे बढ़ने की गुंजाइश कम रह गई। औसतन, 21 ओईसीडी देशों के बीच यह अनुमान है कि 9 प्रतिशत काम के स्वतः होने का जोखिम अधिक है, जबकि अन्य 25 प्रतिशत कामों का स्वतः चालित होने के कारण दुहराव होने की संभावना है (ओईसीडी 2017ख)। अध्ययन यह भी दर्शाते हैं कि कुछ हद तक यह बेचैनी वृहत आर्थिक नीति के समिश्र को दर्शाती है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में पर्याप्त मांग विकास को संपोषित करने में विफल रहा है (ओ ई सी डी, 2017क)।

**व्यापार प्रतिबंधात्मक उपायों में वृद्धि:** हालिया वर्षों में बहुत से व्यापार प्रतिबंधात्मक उपायों में तेजी से वृद्धि हुई है, जिनमें अनेक प्रकार के टैरिफ-भिन्न बाधाएं शामिल हैं। वीजा की नई अड़चनें और व्यक्तियों की गतिविधि के विरुद्ध प्रतिघात का जोखिम चिंता बढ़ाने में आग में घी का काम करता है। जी-20 व्यापार उपायों के संबंध में डब्ल्यूटीओ की 17वीं मॉनीटरिंग रिपोर्ट (30 जून 2017) के अनुसार समीक्षा अवधि (मध्य अक्टूबर 2016 से मध्य मई 2017) के दौरान जी-20 देशों द्वारा कुल 42 नए व्यापार प्रतिबंधात्मक उपाय कार्यान्वित किए गए, जिनमें नया या बढ़ा हुआ टैरिफ, सीमा शुल्क विनियमन और मूल प्रतिबंध के नियम शामिल हैं। मासिक औसत छह उपाय होते हैं। पिछली अवधि की तुलना में यह मामूली वृद्धि दर्शाता है परन्तु 2009-2015 में देखी गई दीर्घावधिक प्रवृत्ति से कम रही जो प्रति माह सात थी। वित्तीय संकट के समय से व्यापार प्रतिबंधात्मक उपायों में लगातार वृद्धि होने से ऐसे प्रतिबंधों से प्रभावित वैश्विक व्यापार के हिस्से में भी धीरे-धीरे वृद्धि हुई है। अक्टूबर मध्य 2016 में, अक्टूबर 2008 से क्रियान्वित किया गया आयात प्रतिबंध उपायों में शामिल किए गए विश्व आयात का हिस्सा 5 प्रतिशत था। और शामिल किया गया जी-20 आयात का हिस्सा 6.5 प्रतिशत था। शुरू किए गए आयात को प्रभावित करने वाले व्यापार प्रतिबंधात्मक उपायों का व्यापार कवरेज पिछली समीक्षा अवधि के दौरान (मध्य अक्टूबर 2016 से मध्य मई 2017) 47 बिलियन अमरीकी डालर था अर्थात जी-20 पण्य वस्तु आयातों के मूल्य का 0.37 प्रतिशत या वैश्विक पण्य वस्तु आयातों के मूल्य का 0.29 प्रतिशत था।

**देशों का भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण:** वैश्वीकरण पर सभी देशों का समान दृष्टिकोण नहीं है। यह हर देश में या देशों के समूह में अलग-अलग है, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है (पीईडब्ल्यू अनुसंधान केन्द्र सर्वेक्षण 2016-17, ओईसीडी 2017ग)।

चार्ट 1. वैश्विक आर्थिक अभिनियोजन पर देशों के भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण ( प्रतिशत )



स्रोत: पीईडब्ल्यू अनुसंधान

टिप्पणी:\* सर्वे किए गए व्यक्तियों का प्रतिशत

- चीनी और भारतीय वैश्वीकरण के बारे में आशावादी हैं चीन में सर्वे किए गए 60 प्रतिशत कहते हैं कि वैश्वीकरण अच्छा है। भारतीयों के मामले में यह 52 प्रतिशत है।
- यूरोप में दृष्टिकोण विभाजित है, नीदरलैंड, स्वीडन, जर्मनी, यू.के., हंगरी और स्पेन में अधिकांश इसका समर्थन करते हैं जबकि ग्रीस, इटली, पोलैंड इसका विरोध करते हैं और फ्रांस दोनों के बीच में है।
- व्यापार संबंधी अमरीकियों के दृष्टिकोण में विपरीत अंतर्ज्ञान विभाजन और परिवर्तनशील है। अधिकांश अमरीकियों के लिए व्यापार प्राथमिकता कभी नहीं रहा यद्यपि वे 2017 में मामूली रूप से अधिक चिंतित हैं। नाफता के लिए अमरीकी जनता का समर्थन हालिया वर्षों में बढ़ा है, यद्यपि नाफता के लिए सरकार का समर्थन कम हुआ है।

## भारत का भुगतान शेष घटनाक्रम

### भुगतान शेष का सिंहवलोकन

6.3 भारत के भुगतान शेष की स्थिति 2013-14 से 2015-16 के दौरान सुहानी और सुखद थी, कम और गिरते व्यापार और चालू खाता घाटा और नरम एवं बढ़ते पूंजी अंतर्वाहों के फलस्वरूप 2016-17 में और अधिक सुधर गई इसके परिणामस्वरूप आरक्षित विदेशी मुद्रा में संग्रहण और अधिक बढ़ गया। यह वैश्विक आर्थिक स्थिति में धीमी सुधार दर्शाता है। दो वर्षों के अंतराल के बाद हुए 2016-17 में भारत का निर्यात 5.2 प्रतिशत पर घनात्मक हो गया। इसके साथ-साथ आयात में 1.0 प्रतिशत की मामूली गिरावट से 2015-16 में 130.1 बिलियन अमरीकी डालर (जीडीपी का 6.2 प्रतिशत) की तुलना में 2016-17 में 112.4 बिलियन अमरीकी डालर (जीडीपी का 5 प्रतिशत) व्यापार घाटा

कम हो गया। अदृश्य शेष 2015-16 में 107.9 बिलियन अमरीकी डालर (जीडीपी का 5.2 प्रतिशत) की तुलना में 2016-17 में 97.1 बिलियन अमरीकी डालर (जीडीपी का 4.3 प्रतिशत) पर कम था। चालू खाता घाटा प्रगामी रूप से घटकर 2015-16 में जीडीपी का 1.1 प्रतिशत से 2016-17 में जीडीपी का 0.7 प्रतिशत पर आ गया। यह व्यापार घाटा तेजी से कम होने के कारण हुआ, जो निवल अदृश्य अर्जन में गिरावट से अधिक है। निवल पूंजी मुख्यतः अंतर्वाह अनिवासी भारतीयों द्वारा जमा राशि में गिरावट के कारण पिछले वर्ष 40.1 बिलियन अमरीकी डालर (जीडीपी का 1.9 प्रतिशत) की तुलना में 2016-17 में 36.8 बिलियन अमरीकी डालर (जीडीपी का 1.6 प्रतिशत) पर मामूली कम था। चूंकि पूंजी खाता अधिशेष चालू खाता घाटा के वित्तपोषण से अधिक था, आरक्षित निधि में (भुगतान शेष आधार पर) 2016-17

में 21.6 बिलियन अमरीकी डालर तक वृद्धि हुई, जो 2015-16 में हुई 17.9 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि से अधिक थी।

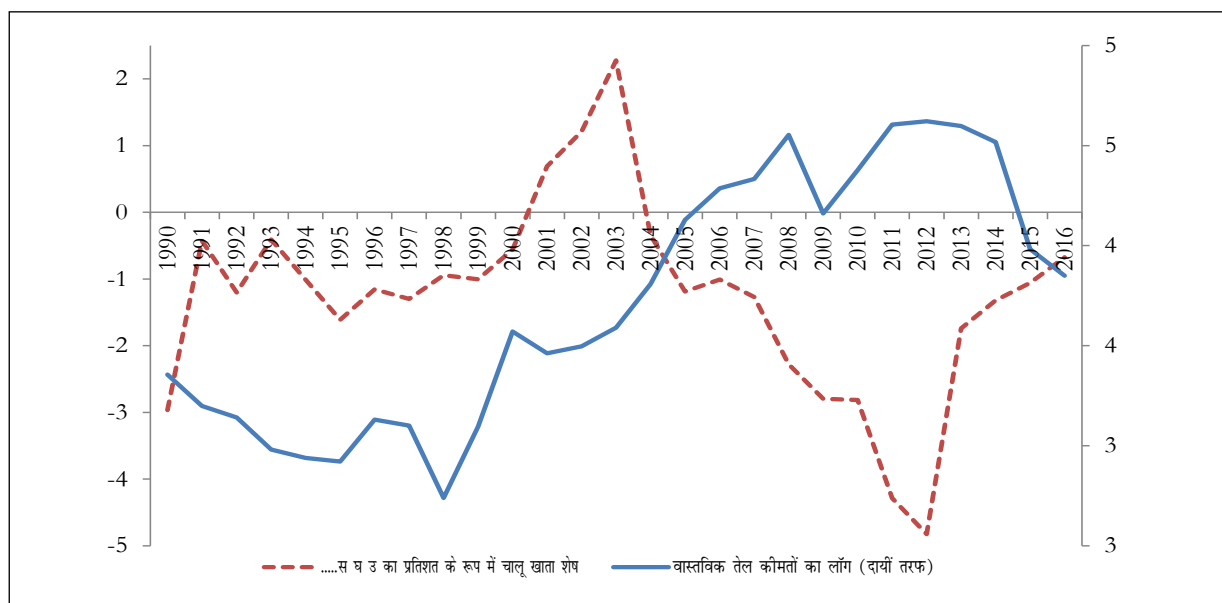
### 2016-17 में चालू खाता घटनाक्रम

#### पण्य वस्तु

6.4 दो वर्षों की ऋणात्मक वृद्धि के बाद, पण्य निर्यात (भुगतान शेष के आधार पर) पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक और पीओएल-भिन्न निर्यातों में धनात्मक वृद्धि के साथ 2016-17 में बढ़कर 5.2 प्रतिशत हो गया। पण्य आयात (भुगतान शेष आधार पर), जोकि 2012-13 से लगातार गिरती रही है, 2016-17 में मामूली रूप से गिरकर 1.0 प्रतिशत हो गया। निर्यातों में आई वृद्धि और आयातों में हुई गिरावट के साथ व्यापार घाटा 13.6

प्रतिशत तक कम हुआ। पहली छमाही में आयात में हुई तेज गिरावट और दूसरी छमाही में निर्यातों में हुई वृद्धि ने 2016-17 में लगभग 18 बिलियन अमरीकी डालर का व्यापार घाटा कम करने में भारत की मदद की है। अप्रैल-दिसंबर 2016-17 में अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल कीमतों में हुई गिरावट भारतीय समूह के कारण तेल आयात बिल में लगभग 10 प्रतिशत गिरावट साथ ही स्वर्ण आयातों में तेज गिरावट के साथ हो गई भारत के समग्र आयात में गिरावट आई। 2014-15 में कच्चे तेल कीमतों में तेज गिरावट भारत के चालू खाता घाटा में गिरावट की एक प्रमुख वजह रही है। (चित्र 1) तथापि, 2016-17 की चौथी तिमाही में आयात में तेज वृद्धि हुई थी क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें एक वर्ष पूर्व के अपने स्तर से बढ़ गई थी।

चित्र 1. चालू खाता शेष और वास्तविक तेल की कीमत का लॉग



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक और विश्व बैंक के आंकड़े पर आधारित

6.5 भारत का पण्य वस्तु निर्यात (सीमा शुल्क आधार पर) 2013-14 में यद्यपि केवल 4.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 314.4 बिलियन अमरीकी डालर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। निर्यात वृद्धि में गिरावट की वैश्विक प्रवृत्ति के बाद 2014-15 और 2015-16 के दौरान, भारत की निर्यात वृद्धि भी कम होकर क्रमशः 1.3 प्रतिशत और 15.5 प्रतिशत रह गयी। 2016-17 की पहली छमाही में भारत की निर्यात वृद्धि ऋणात्मक बनी रही। तथापि, 2016-17 की दूसरी छमाही में, इसमें धनात्मक वृद्धि

दर्ज हुई इसके परिणामस्वरूप पूरे वर्ष 2016-17 के दौरान 5.3 प्रतिशत की धनात्मक वृद्धि के साथ 276.5 बिलियन अमरीकी डालर हो गया (सारणी 2)।

6.6 भारत के निर्यात में वृद्धि (ईंधन-भिन्न) जो सामान्यतः विश्व निर्यात वृद्धि (ईंधन-भिन्न) के मुकाबले अधिक रहा है, 2014 में ऋणात्मक हो गई और यह तबसे कमतर रही अथवा विश्व निर्यात वृद्धि (ईंधन-भिन्न) के क्रम में रही (चित्र 2)।

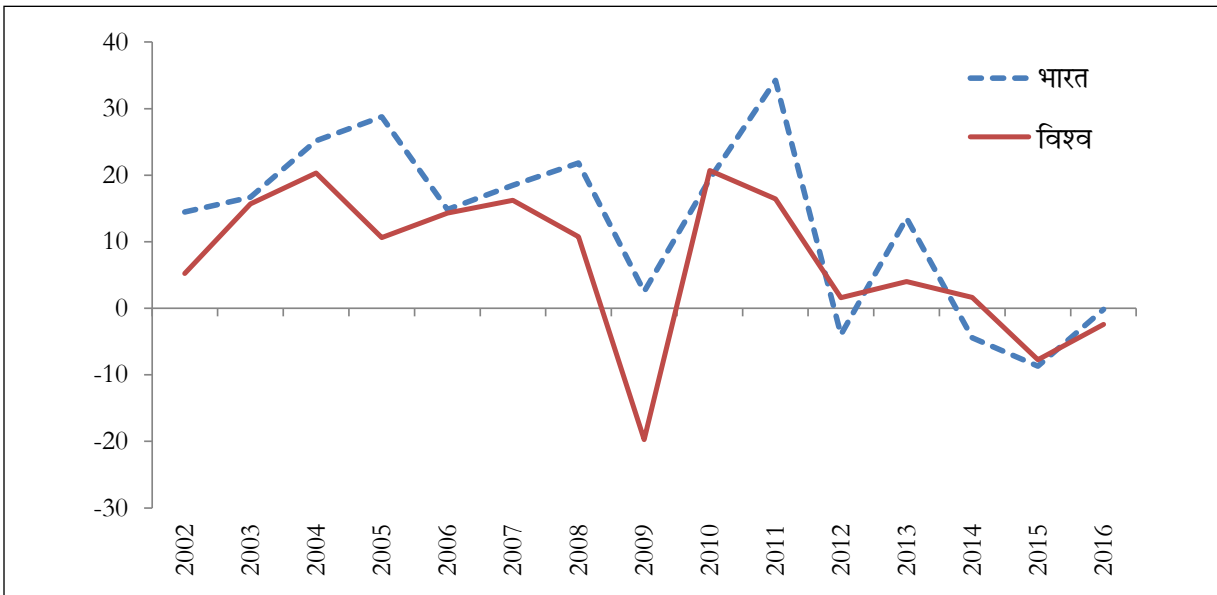
## सारणी 2. व्यापार निष्पादन

	बिलियन अमरीकी डालर में मूल्य		वृद्धि (वर्षानुवर्ष) प्रतिशत में	
	2016-17	2015-16	2016-17	2017-18 (अप्रैल-जून)
निर्यात	276.3	-15.5	5.3	10.6
पीओएल निर्यात	31.7	-46.2	3.7	20.4
पीओएल निर्यात-भिन्न	244.6	-8.6	5.6	9.4
आयात	384.3	-15.0	0.9	32.8
पीओएल आयात	86.9	-40.0	4.8	23.0
पीओएल आयात-भिन्न	297.4	-3.8	-0.2	35.6
सोना व चांदी आयात	29.3	-8.8	-17.3	176.3
पीओएल-भिन्न व सोना व चांदी-भिन्न आयात	268.1	-3.0	2.1	25.0
<b>व्यापार शेष</b>	<b>-108.0</b>	<b>-13.8</b>	<b>-9.0</b>	<b>108.2</b>

स्रोत: वाणिज्य विभाग का आंकड़े पर आधारित

\*अध्यतन प्रेस विज्ञापित पर आधारित

चित्र 2. विश्व और भारत के (ईंधन-भिन्न निर्यात मूल्य वृद्धि (प्रतिशत))



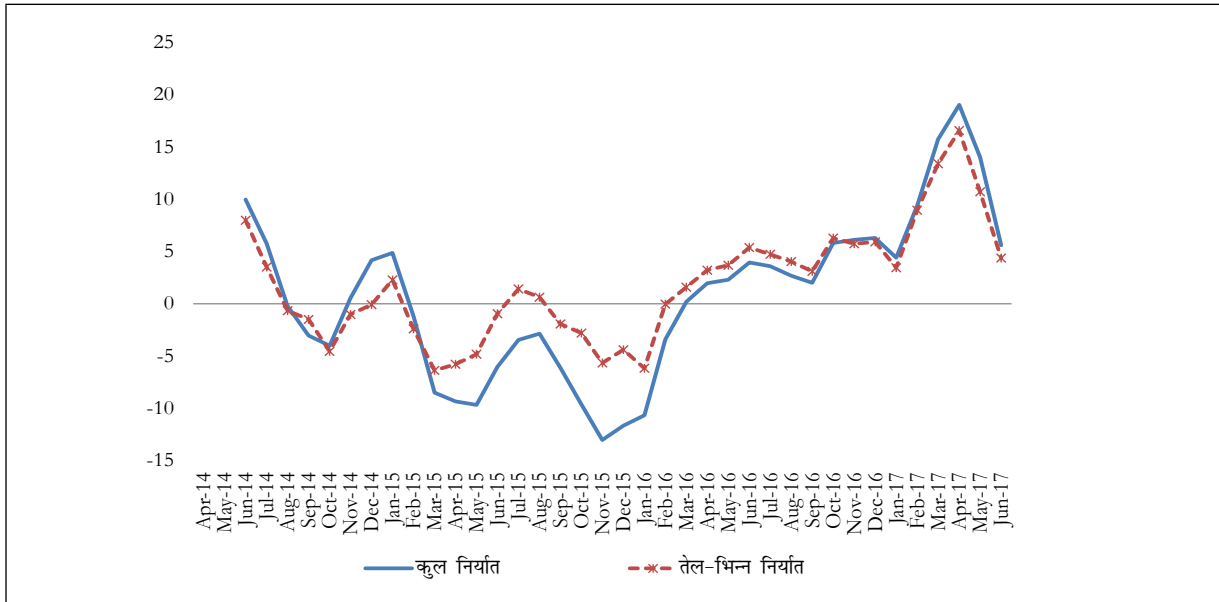
स्रोत: आईटीसी व्यापार मानचित्र पर आधारित

6.7 2016-17 में भारत की धनात्मक निर्यात वृद्धि पीओएल और पीओएल-भिन्न दोनों में धनात्मक वृद्धि क्रमशः 3.7 प्रतिशत और 5.6 प्रतिशत के चलते हुई। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के साथ, पीओएल निर्यात वृद्धि 25.8 प्रतिशत पर 2016-17 की दूसरी छमाही में 10 प्रतिशत की पीओएल निर्यात वृद्धि के दुगुना से अधिक रही। 2017-18 (अप्रैल-जून) में, पीओएल-भिन्न निर्यात में दुगुना वृद्धि होने के कारण पीओएल निर्यात में 10.6 प्रतिशत पर द्विअंकीय वृद्धि हुई।

6.8 दिसंबर, 2015 में पीओएल और पीओएल-भिन्न निर्यात दोनों की प्रमात्रा में हुई वृद्धि जोकि फरवरी, 2016 में धनात्मक हुई, इससे निर्यात में सुधार आने में मदद मिली यद्यपि, मई और जून 2017 में मामूली गिरावट रही (चित्र 3)।

6.9 भारत का पण्य आयात भी (सीमा शुल्क आधार पर) वर्ष 2012-13 के 490.7 बिलियन अमरीकी डालर के उच्च स्तर से गिरकर वर्ष 2015-16 में 381.0 बिलियन अमरीकी डालर हो गया और वर्ष 2016-17

चित्र 3. निर्यातों की प्रमात्रा सूचकांक में वृद्धि 3 एमएमए ( प्रतिशत ) 2013-14=100

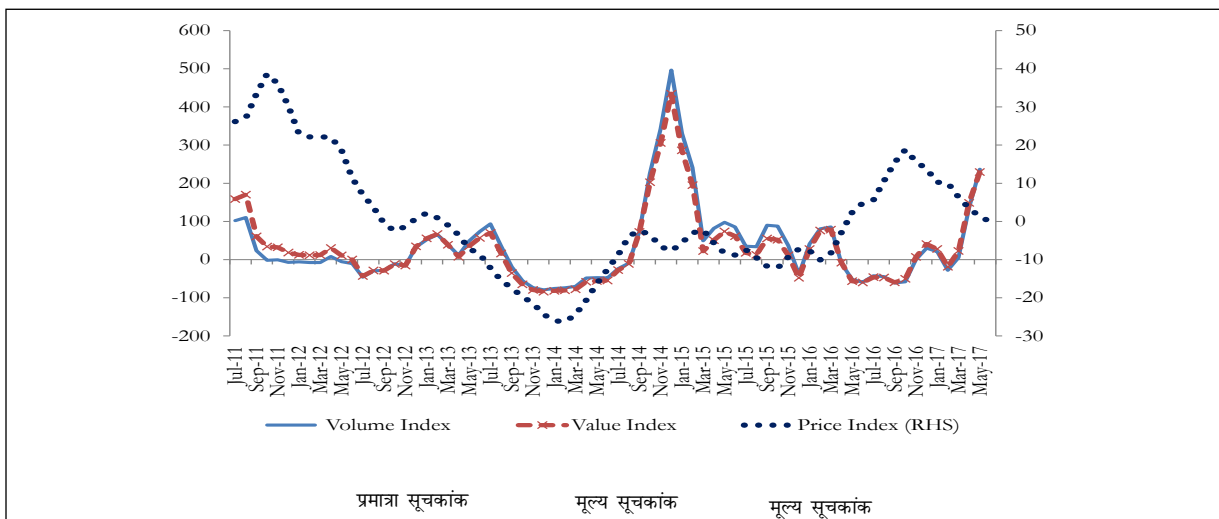


स्रोत: आंतरिक परिकलन। डीजीसीआईएण्डएस के मासिक व्यापार आंकड़े, डालर के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय मूल्य सूचकांक की संगणना के लिए विश्व बैंक मासिक पीक शीट, रुपया सूचकांक को डालर सूचकांक में परिवर्तित करने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय थोक मूल्य सूचकांक और आरबीआई विनिमय दर

में 0.9 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की गई और 384.3 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। सोने और चांदी के आयात में 17.3 प्रतिशत की मामूली गिरावट के बावजूद, वर्ष 2016-17 में पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक के आयात में बढ़ोत्तरी और पीओएल-भिन्न और स्वर्ण-भिन्न और चांदी के आयात में मामूली वृद्धि हुई। तथापि, वर्ष 2017-18 (अप्रैल-जून) में, 23.0 प्रतिशत

पर पीओएल आयात वृद्धि के साथ आयात बढ़कर 32.8 प्रतिशत हो गया। यह मुख्यतया कच्चे तेल के कीमतों में बढ़ोत्तरी के चलते हुआ और पीओएल-भिन्न आयात वृद्धि 35.6 प्रतिशत हुई जो सोने और चांदी के आयातों में 176.3 प्रतिशत पर उच्च वृद्धि और पीओएल-भिन्न और स्वर्ण-भिन्न और चांदी आयात 25 प्रतिशत बढ़ने के कारण हुई। स्वर्ण आयातों के मूल्य में बढ़ोत्तरी स्वर्ण

चित्र 4. स्वर्ण प्रमात्रा के आयात/मूल्य और स्वर्ण मूल्य में वृद्धि, 3एमएमए ( प्रतिशत ) ( 2010-11=100 )

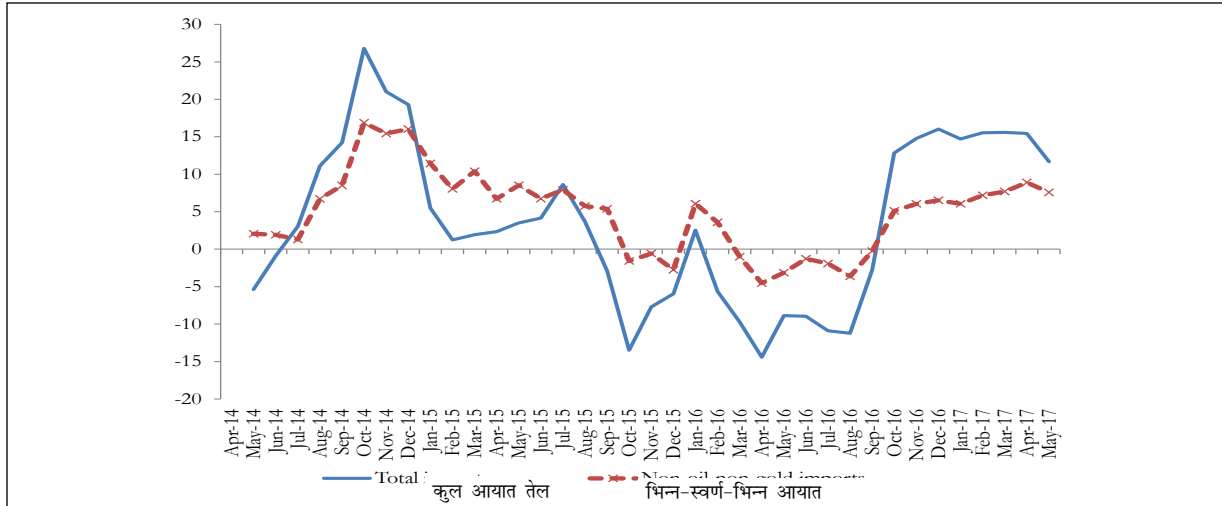


स्रोत: डीजीसीआई एण्ड सी मासिक आंकड़ा से परिकलित

आयातों की प्रमात्रा में वृद्धि के चलते हुई। वस्तुतः स्वर्ण आयात मूल्य सूचकांक पिछले वर्षों से स्वर्ण प्रमात्रा सूचकांक के क्रम में बढ़ रहा है।

6.10 आयात प्रमात्रा में वृद्धि, कुल और तेल-भिन्न और स्वर्ण-भिन्न (3एमएमए) दोनों अक्टूबर, 2016 से धनात्मक रही हैं यद्यपि, जून 2017 में मामूली गिरावट आई है (चित्र 5)।

चित्र 5. आयातों की प्रमात्रा सूचकांक में वृद्धि: 3 एमएमए (प्रतिशत) 2013-14=100



स्रोत: चित्र 3 के अनुसार

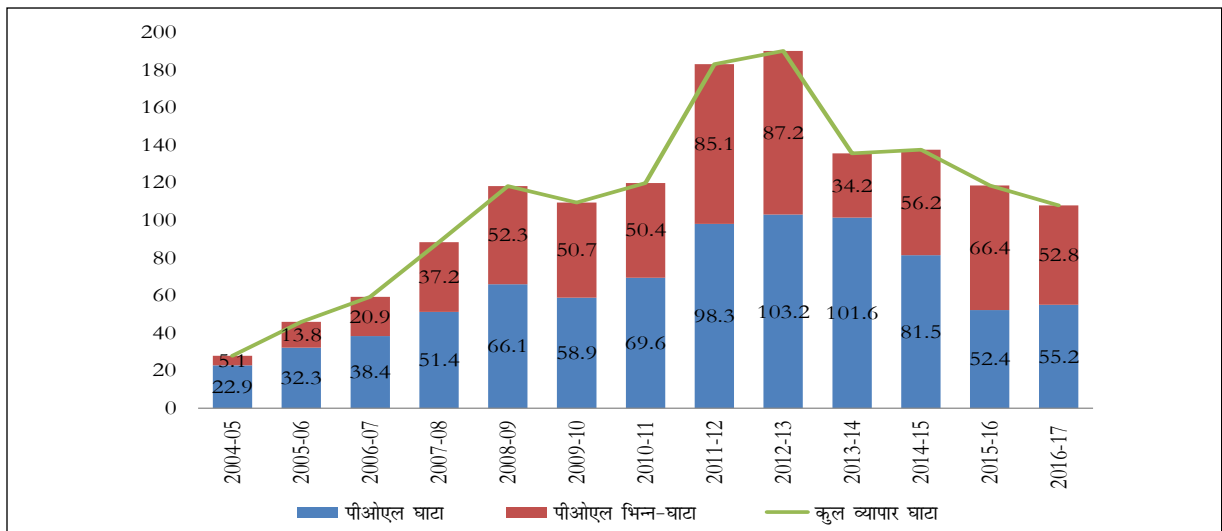
**व्यापार घाटा**

6.11 भारत का व्यापार घाटा (सीमा शुल्क आधार पर), जोकि वर्ष 2004-05 से लगातार बढ़ा और वर्ष 2012-13 में 190.3 बिलियन अमरीकी डालर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, इसमें वर्ष 2014-15 से लगातार गिरावट दर्ज की गई, जो वर्ष 2016-17 में 108.0 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर पहुंच गया। पीओएल घाटा और पीओएल-भिन्न घाटा दोनों में वर्ष

2013-14 से सामान्य गिरावट आई यद्यपि इन दोनों में कुछ वर्षों में घट-बढ़ होते रहा (चित्र 6)।

पीओएल, भिन्न घाटा में गिरावट मुख्यतया निवल जेवरात और ज्वेलरी घाटे में 2014-15 में 21.1 बिलियन अमरीकी डालर से 2015-16 में 17.2 बिलियन अमरीकी डालर की कमी और 2016-17 में और अधिक 10.3 बिलियन अमरीकी डालर तक गिरावट के कारण रही।

चित्र 6. पीओएल और पीओएल-भिन्न व्यापार घाटा ( बिलियन अमरीकी डालर )



स्रोत: डीजीसीआई एण्ड एस के आंकड़ों से परिकल्पित



तथापि, 2017-18 (अप्रैल-जून) में उच्च आयात वृद्धि के साथ व्यापार घाटा बढ़कर 108.2 प्रतिशत हो गया जबकि निर्यात वृद्धि कम रही जैसाकि पहले दर्शाया गया है।

6.12 भारत के व्यापार भागीदारों में, शीर्ष पांच देशों, जिनके साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार शेष ऋणात्मक है वे हैं: चीन, स्विटजरलैंड, सऊदी अरब, ईराक और

इंडोनेशिया, जबकि शीर्ष पांच देशों, जिनके साथ भारत का अधिशेष व्यापार शेष है वे हैं: यूएसए, यूई, बंगलादेश, हांगकांग और नेपाल। भारत के कुल व्यापार घाटा में प्रमुख योगदानकर्ता चीन के साथ इसका व्यापार घाटा है, जिसका हिस्सा 2011-12 में 20.3 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 47.3 प्रतिशत हो गया है।

**सारणी 3. द्विपक्षीय व्यापार अधिव्य/घाटा ( बिलियन अमरीकी डालर )**

		2011-12	2014-15	2015-16	2016-17 (P)
व्यापार अधिव्य वाले देश	संयुक्त रा० अमेरिका	11.4	20.6	18.6	20.0
	यू०ए०ई०	-0.8	6.9	10.8	9.8
	बंगलादेश	3.2	5.8	5.3	6.0
	हांगकांग	2.5	8.0	6.0	6.0
	नेपाल	2.2	3.9	3.5	5.0
व्यापार घाटा वाले देश	चीन	-36.6	-48.5	-52.7	-51.1
	स्वीटजरलैंड	-34.1	-21.1	-18.3	-16.3
	सऊदी अरब	-26.4	-16.9	-13.9	-14.8
	ईराक	-18.2	-13.4	-9.8	-10.6
	इंडोनेशिया	-8.2	-11	-10.3	-9.9
<b>कुल व्यापार घाटा</b>		<b>-183.4</b>	<b>-137.6</b>	<b>-118.7</b>	<b>-108.0</b>

स्रोत: वाणिज्य विभाग डाटाबेस

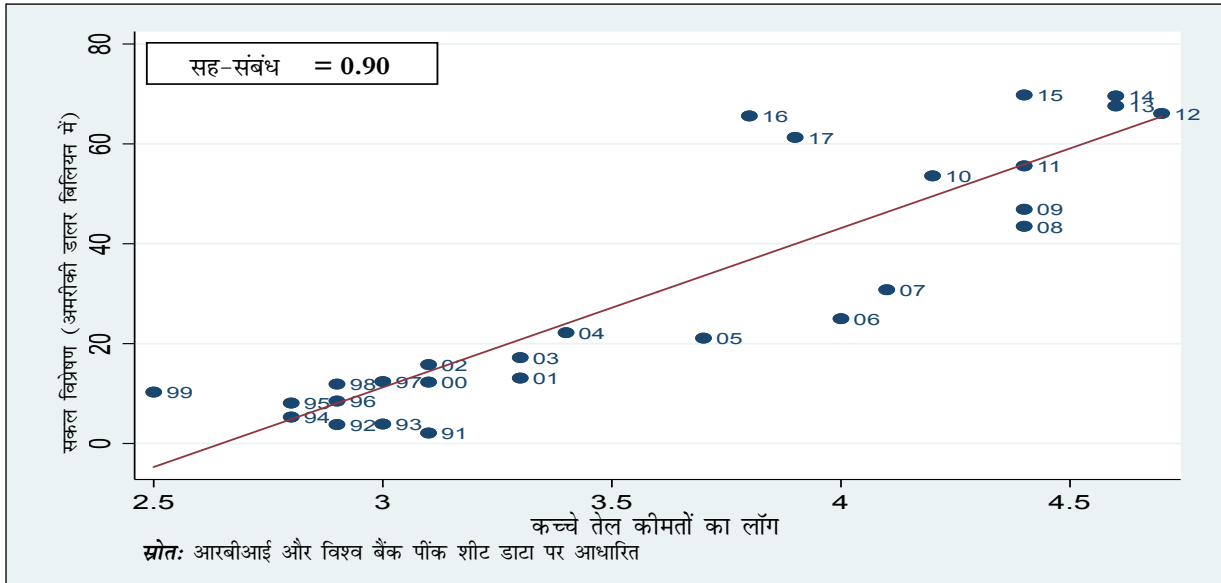
### अदृश्य और निवेश से आय

6.13 निवल अदृश्य प्राप्तियां, निवल सेवाओं और निवल निजी अंतरणों दोनों में गिरावट के साथ 2016-17 में 10 प्रतिशत गिरकर 97.1 बिलियन अमरीकी डालर रह गई। निवल सेवाएं जोकि व्यापार घाटा के प्रभाव को कम करने के लिए सहायक के रूप में कार्य करती हैं, 3.2 प्रतिशत से गिरकर 67.5 बिलियन अमरीकी डालर हो गई। यह मुख्यतया सॉफ्टवेयर, बीमा और पेंशन सेवाएं और वित्तीय सेवाओं के खाते पर निवल भुगतान, बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के प्रयोग हेतु प्रभार और वैयक्तिक, सांस्कृतिक एवं मनोरंजक सेवाओं के निवल प्राप्तियों में गिरावट के कारण हुई। स्रोत देशों खासतौर पर खाड़ी क्षेत्रों में कम आय की परिस्थितियों, तेल कीमतों में उत्तरोत्तर वृद्धि के चलते विदेशों में तैनात भारतीयों द्वारा विप्रेषण कम हुआ। सरल सह-संबंध विश्लेषण तेल कीमतों और विप्रेषणों

के बीच एक मजबूत घनात्मक सह-संबंध को दर्शाता है (चित्र 7)। विश्व बैंक के आब्रजन और विकास सार 27 (अप्रैल, 2017) के अनुसार, 2015 में 1 प्रतिशत की गिरावट के बाद, विप्रेषणों वाले विकासशील देशों में विप्रेषण प्रवाहों के इतिहास में पहली बार लगातार दो वर्षों में गिरावट देखी गई जोकि 2016 में 2.4 प्रतिशत गिरकर 429 बिलियन अमरीकी डालर होने का अनुमान है। 2009 में, वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान, जबकि विकासशील देशों में विप्रेषण प्रवाह लगभग 5 प्रतिशत घट गया यह एक वर्ष के भीतर दोबारा बढ़ने लगा। सामान्य प्रवृत्ति के समरूप, भारत को निवल निजी अंतरण भी 2014-15 में 66.3 बिलियन अमरीकी डालर से गिरकर 2015-16 में 63.1 बिलियन अमरीकी डालर और 2016-17 में 56.6 बिलियन अमरीकी डालर पर आ गया।



चित्र 7. विप्रेषण और तेल कीमतों का लॉग



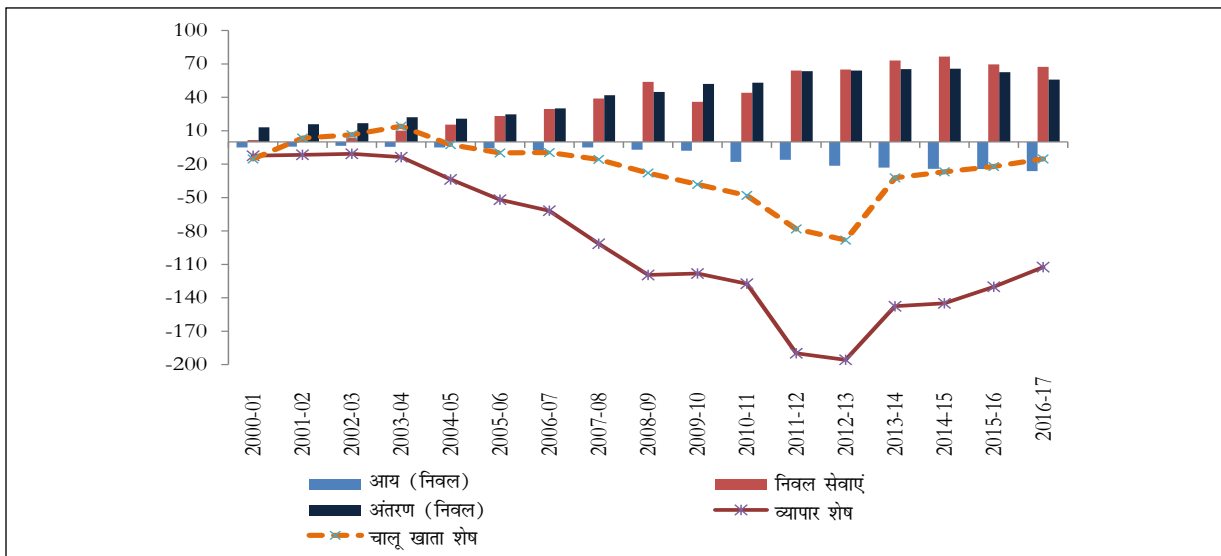
6.14 निवल निवेश आय के कारण बहिर्प्रवाह जो पिछले वर्षों से लगातार बढ़ रहा है और 7.9 प्रतिशत बढ़कर 26.3 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। 2016-17 में कमतर व्यापार घाटा के परिणामस्वरूप चालू खाता घाटा कम होकर 15.3 बिलियन अमरीकी डालर (जीडीपी का 0.7 प्रतिशत) हो गया (चित्र 8)।

**2016-17 में पूंजी/वित्त लेखे की गतिविधि**

6.15 2016-17 में चालू खाता घाटा निवल पूंजी प्रवाह द्वारा आसानी से वित्त पोषित होता रहा जिसमें विदेशी

प्रत्यक्ष निवेश का हिस्सा अधिक था। भारत में सकल एफडीआई अंतर्वाह 2015-16 में 55.6 बिलियन अमरीकी डालर से महत्वपूर्ण रूप से बढ़कर 2016-17 में 60.2 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। निवल एफडीआई अंतर्वाह (अर्थात् बहिर्प्रवाह एफडीआई का निवल) 35.6 बिलियन अमरीकी डालर रहा फिर भी 2015-16 में मामूली रूप से 1.1 प्रतिशत कम होकर 36.6 बिलियन अमरीकी डालर रह गया। निवल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश प्रवाह की वैश्विक और घरेलू घटनाक्रम दोनों में अधोमुखी रहा जिसके कारण घरेलू पूंजी बाजार

चित्र 8. भुगतान शेष के घटक



स्रोत: आरबीआई आंकड़ा पर आधारित

में उतार-चढ़ाव रहा। अस्थिर उतार-चढ़ाव ब्रेकजीट अवधि, यूएस के राष्ट्रपति चुनाव परिणाम, विमुद्रीकरण और यूएस फेडरल रॉलिसी रेट की अवधि के दौरान दिखाई दिया। पोर्टफोलियो निवेश में 2016-17 में 7.6 बिलियन अमरीकी डालर का निवल अंतर्वाह दर्ज किया गया जबकि एक वर्ष पूर्व 4.1 बिलियन अमरीकी डालर का बहिर्प्रवाह था। 2016-17 अप्रैल-दिसंबर के दौरान महत्वपूर्ण बहिर्प्रवाह के पश्चात् 2016-17 की चौथी तिमाही में घरेलू पूंजी बाज़ार में पोर्टफोलियो क्रैताओं का निवेश ब्याज बढ़ा। 2017-18 में (16 जूलाई, 2017 तक) 2016-17 की तदनु रूप अवधि में 2.1 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 13.5 बिलियन अमरीकी

डालर का निवल एफडीआई अंतर्प्रवाह अधिक रहा। 2016-17 में पूंजी प्रवाह के अन्य प्रकारों में, बैंकिंग पूंजी ने 16.6 बिलियन अमरीकी डालर का निवल बहिर्प्रवाह दर्ज किया, यह मुख्यतया सितम्बर से नवम्बर, 2016 के दौरान बैंकों और एफसीएनआर (बी) निक्षेपों के उन्मोचन द्वारा विदेशी अस्तियों के बढ़ने के चलते रहा। विदेशी वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) के मामले में 2016-17 में 6.1 बिलियन अमरीकी डालर का निवल बहिर्प्रवाह हुआ क्योंकि नए उधारों की तुलना में पुनर्भुगतान अधिक हुआ। चूंकि निवल पूंजी अंतर्प्रवाह से पर्याप्त रूप से चालू खाता घाटा का वित्त पोषित किया गया, भारत के विदेशी मुद्रा भण्डार में निवल वृद्धि हुई (सारणी 4)।

**सारणी 4. भारत का भुगतान शेष का सार**

( बिलियन अमरीकी डालर )

मद	2014-15	2015-16	2016-17 P
<b>I चालू खाता</b>			
i. निर्यात	316.5	266.4	280.1
ii. आयात	461.5	396.4	392.6
iii. व्यापार शेष	-144.9	-130.1	-112.4
iv. अदृश्य (निवल)	118.1	107.9	97.1
(क) सेवाएं	76.5	69.7	67.5
(ख) अंतरण	65.7	62.6	56
(ग) आय	-24.1	-24.4	-26.3
चालू खाता शेष	-26.9	-22.2	-15.3
<b>II पूंजी खाता</b>			
i. विदेशी सहायता (निवल)	1.7	1.5	2.0
ii. विदेशी वाणिज्यिक उधार (निवल)	1.6	-4.5	-6.1
iii. अल्पावधिक ऋण	-0.1	-1.6	6.5
iv. बैंकिंग पूंजी (निवल) जिसमें	11.6	10.6	-16.6
v. निवासी निक्षेप (निवल)	14.1	16.1	-12.4
vi. विदेशी निवेश (निवल)	73.5	31.9	43.2
जिसमें			
(क) एफडीआई (निवल)	31.3	36	35.6
(ख) पोर्टफोलियो (निवल)	42.2	-4.1	7.6
IV. अन्य प्रवाह (निवल)	1.0	3.2	7.5
पूंजी खाता शेष	89.3	41.1	36.5
<b>III भूल-चूक</b>	-1.0	-1.1	0.4
पूंजी खाता शेष (भूल-चूक)	88.3	40.1	36.8
<b>IV समग्र शेष</b>	61.4	17.9	21.6
<b>V रिज़र्व परिवर्तन वृद्धि ( - )/कमी ( + ),</b>	-61.4	-17.9	-21.6

स्रोत: आरबीआई

टिप्पण: अंशः अंशतः संशोधित; अः अनंतिम

6.16 कमतर चालू खाता घाटा, सकल एफडीआई अंतर्प्रवाह का बढ़ना, एफसीएनआर (बी) डालर निधियों का सरल और सफलतापूर्वक उन्मोचन और विदेशी मुद्रा रिजर्व का मजबूत निर्माण सभी यह दर्शाते हैं कि भारत का भुगतान शेष बेहदरी के लिए स्थिर हो सकता है। फ्लिप पक्ष पर भी, व्यापार घाटा जो कि व्यापार के पक्षपूर्ण संदर्भ के चलते गिरावट आई में, वैश्विक जिस कीमतों में वृद्धि हुई है, विप्रेषणों में लगभग आनुपातिक वृद्धि हो सकती है।

### व्यापार का संघटन

6.17 वर्ष 2016-17 में निर्यात वृद्धि मोटे तौर पर प्रमुख वस्तुओं में सकारात्मक वृद्धि पर आधारित थी, चर्म और चर्म उत्पादों में 4.1 प्रतिशत तक, वस्त्रों में 2.2 प्रतिशत तक गिरावट और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं तथा दवाइयों और

औषधों में मामूली गिरावट को छोड़कर (सारणी 5)। छह प्रमुख निर्यात क्षेत्रों में, अभियांत्रिकी सामान और रत्न तथा आभूषण क्षेत्रों में अच्छी वृद्धि हुई; पेट्रोलियम क्रूड एवं इसके उत्पादों और रसायनों तथा इनसे संबंधित उत्पादों में कम वृद्धि हुई; कृषि एवं तत्संबंधित उत्पादों में मामूली सकारात्मक वृद्धि हुई; और कपड़ा तथा तत्संबंधित उत्पादों में मामूली नकारात्मक वृद्धि हुई। उच्च वृद्धि वाले अन्य निर्यात क्षेत्र समुद्री उत्पाद और खनिज थे। वर्ष 2016-16 में क्षेत्रों द्वारा निर्यात वृद्धि के लिए बिंदु की दृष्टि से योगदान के तहत, अभियांत्रिकी सामान से योगदान सर्वोच्च (46.9 प्रतिशत) था, इसके बाद रत्न और आभूषण (29.9 प्रतिशत), अयस्क और खनिज (8.4 प्रतिशत), समुद्री उत्पाद (8.1 प्रतिशत) और पेट्रोलियम उत्पाद (7.3 प्रतिशत) का स्थान था।

### सारणी 5. निर्यातों का क्षेत्रवार हिस्सा और वृद्धि दर

क्रम सं.	क्षेत्र	हिस्सा ( प्रतिशत )		वृद्धि दर ( प्रतिशत )	
		2015-16	2016-17 (अ.)	2015-16	2016-17 (अ.)
1	अभियांत्रिकी वस्तुएं	23.1	24.3	-17.2	10.8
2	रत्न तथा आभूषण	15.0	15.8	-4.8	10.9
3	रसायन और इनसे संबंधित उत्पाद**	14.7	14.3	0.6	2.1
	जिनमें से				
	दवाइयां और औषध	6.5	6.1	9.6	-0.4
4	कपड़ा और तत्संबंधित उत्पाद	13.7	13.0	-3.2	-0.1
	जिनमें से				
	कपड़ा	5.6	5.2	-8.5	-2.2
	परिधान	8.1	7.8	0.8	1.3
5	पेट्रोलियम क्रूड एवं उत्पाद	11.7	11.5	-46.2	3.7
6	कृषि और तत्संबंधित उत्पाद *	9.9	9.5	-17.6	0.9
7	इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं	2.2	2.1	-5.3	-0.1
8	समुद्री उत्पाद	1.8	2.1	-13.5	24.2
9	अयस्क और खनिज	0.8	1.2	-16.4	59.1
10	चर्म और चर्मनिर्मित उत्पाद	2.1	1.9	-10.3	-4.1
	<b>कुल निर्यात ( अन्य सहित )</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-15.5</b>	<b>5.3</b>

स्रोत: वाणिज्य विभाग आंकड़ा आधार से परिगणित। अ.: अनंतिम  
टिप्पणी: \*बागान सहित। \*\*प्लास्टिक और रबर उत्पादों सहित।

6.18 क्षेत्रवार प्रमुख महत्वपूर्ण मदों में से एक मद, पीओएल के आयातों में मुख्य रूप से 2013-14 और 2014-15 में आई तीव्र गिरावट के बाद अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत (भारतीय समूह) में 2015-16 में 46.2 अमरीकी डालर /बीबीएल से वर्ष 2016-17 में 47.6 अमरीकी डालर/बीबीएल तक की मामूली बढ़ोतरी के कारण वर्ष 2016-17 में 4.8 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। वर्ष 2016-17 में अन्य महत्वपूर्ण आयात मदों में, इलेक्ट्रॉनिक सामान, अयस्क और खनिज में निम्न वृद्धि दर्ज की गई, हालांकि कोयले, कोक और कोयला निर्मित ईटों में उच्च वृद्धि दर्ज की गई; तथा

कृषि और तत्संबंधी उत्पादों में उच्च वृद्धि दर्ज की गई। रसायनों और तत्संबंधी उत्पादों में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। पूंजीगत सामान के आयात में मामूली गिरावट आई हालांकि उप-श्रेणी के परिवहन उपस्करों में उच्च सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। मुख्य रूप से निर्यात और विनिर्माण के लिए प्रयुक्त मोतियों और बहुमूल्य रत्नों के आयात में उच्च सकारात्मक वृद्धि दर्ज होने के बावजूद सोने और चांदी के आयात में नकारात्मक वृद्धि के कारण रत्न और आभूषण के आयात में 4.9 प्रतिशत तक की गिरावट आई (सारणी 6)।

### सारणी 6. आयात का क्षेत्रवार हिस्सा और वृद्धि दर

क्रम सं०	क्षेत्र	हिस्सा ( प्रतिशत )		वृद्धि दर ( प्रतिशत )	
		2015-16	2016-17 (अ.)	2015-16	2016-17 (अ.)
1	पेट्रोलियम तेल और स्नेहक	21.8	22.6	-40.0	4.8
2	पूंजीगत सामान	21.1	20.7	-2.5	-1.5
	जिनमें से				
	मशीनरी	8.7	8.5	3.7	-1.3
	आधार धातु	6.5	5.6	-8.7	-12.8
	परिवहन उपस्कर	4.0	5.1	0.7	27.3
3	रत्न एवं आभूषण	14.8	14.0	-9.4	-4.9
	जिनमें से				
	स्वर्ण	8.3	7.2	-7.7	-13.4
	मोती और अर्द्ध कीमती रत्न	5.3	6.2	-11.2	18.6
	चांदी	1.0	0.5	-17.3	-50.9
4	रसायन और तत्संबंधी उत्पाद**	13.3	12.4	-4.2	-5.8
	जिनमें से				
	कार्बनिक रसायन	2.5	2.6	-15.2	2.7
	उर्वरक	2.1	1.3	9.1	-37.7
5	इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं	10.5	11.0	8.6	4.8
6	कृषि और तत्संबंधी उत्पाद*	5.7	6.3	7.7	11.4
7	अयस्क और खनिज	5.4	5.6	-23.2	4.5
	जिनमें से				
	कोयला, कोक और कोयला निर्मित ईटे	3.6	4.1	-23.2	15.2
	<b>कुल आयात ( अन्य सहित )</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-15.0</b>	<b>0.9</b>

स्रोत: वाणिज्य विभाग आंकड़ा आधार से परिगणित। अ.: अनंतिम

टिप्पणी: \*समुद्री उत्पादों और बागान सहित, \*\*प्लास्टिक और रबर उत्पादों सहित।

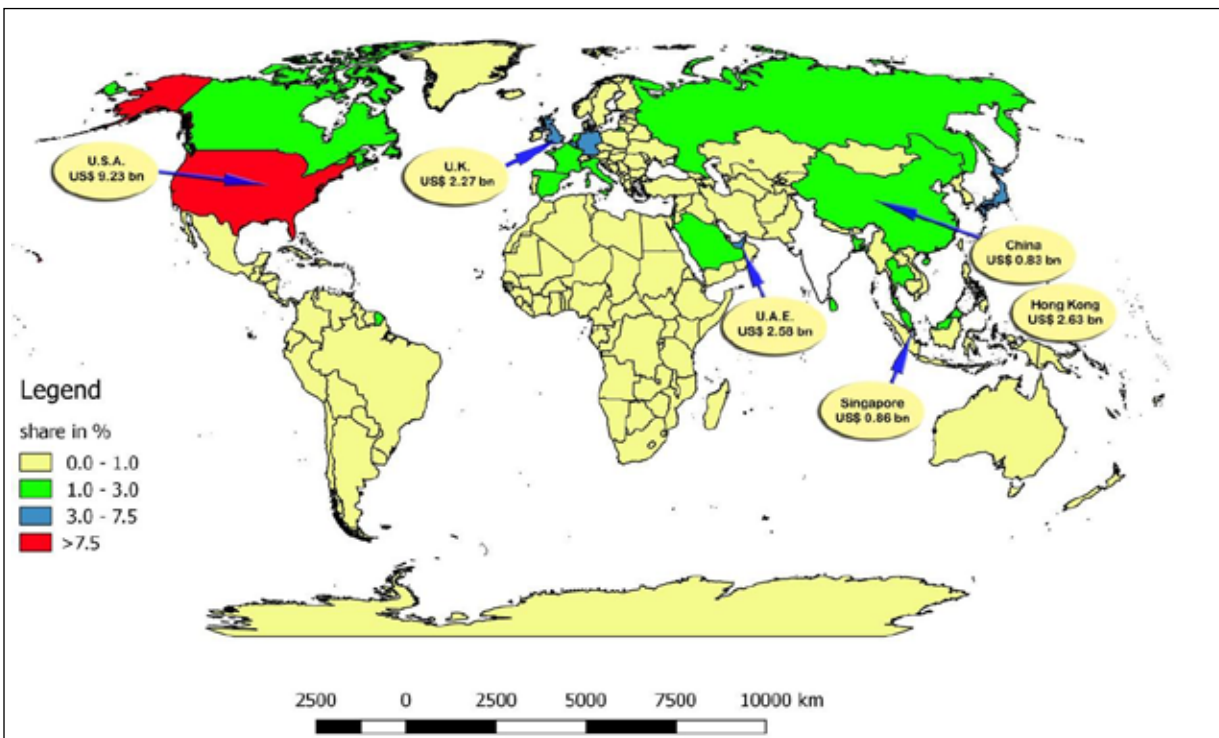
### व्यापार की दिशा

6.19 वर्ष 2016-17 में क्षेत्रवार, एशिया को भारत के निर्यात (50 प्रतिशत के निर्यात हिस्से के साथ) में 8.0 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। इसी प्रकार, यूरोप, अमरीका और बाल्टिक्स को भारत के निर्यात (क्रमशः 19.2 प्रतिशत, 19.9 प्रतिशत और 1.0 प्रतिशत के हिस्से के साथ) में 5.5 प्रतिशत, 4.4 प्रतिशत और 16.8 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। तथापि, अफ्रीका को भारत के निर्यात में नकारात्मक वृद्धि दर देखी गई। 2016-17 में भारत के प्रमुख निर्यात गंतव्यों में, सभी तीन शीर्ष गंतव्यों, अर्थात संयुक्त राज्य अमरीका के बाद संयुक्त अरब अमीरात और हांगकांग को भारत के निर्यात में क्रमशः 5.0 प्रतिशत, 3.4 प्रतिशत और 17.1 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। इसके विपरीत यूके, सऊदी अरब और जापान को भारत के निर्यात में क्रमशः 3.1 प्रतिशत, 19.7 प्रतिशत और 17.3 प्रतिशत तक गिरावट आई। चीन, जो वर्तमान में चौथा बड़ा गंतव्य है, को भारत का निर्यात 13.1 प्रतिशत तक बढ़ गया। वस्तुतः, वर्ष 2016-17 में भारत के कुल निर्यात में केवल 2 देशों को भारत के निर्यात का हिस्सा 7.5 प्रतिशत से अधिक है और 4 देशों को इसका हिस्सा 3 से 7.5 प्रतिशत तक है। वर्ष 2000-01

से 2016-17 के बीच भारत के व्यापार की दिशा में परिवर्तन मुख्य रूप से संयुक्त अरब अमीरात के मामले में उपर्युक्त 7.5 प्रतिशत की श्रेणी से एक स्टेप ऊपर तथा चीन और सिंगापुर के मामले में 3-7.5 प्रतिशत की श्रेणी में जाने से हुआ है (चित्र 9क और 9ख)।

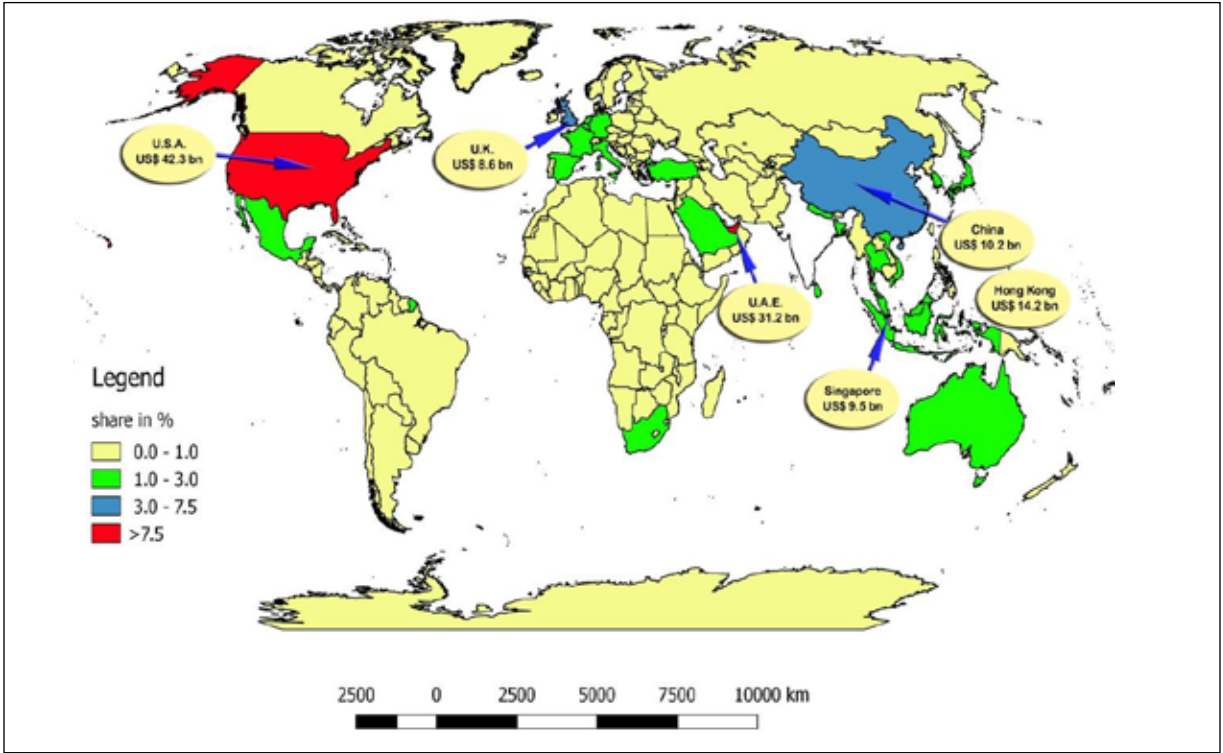
6.20 वर्ष 2016-17 में आयात के मामले में 60.0 प्रतिशत के हिस्से के साथ एशिया आयात का प्रमुख स्रोत बना रहा, इसके बाद यूरोप (16.0 प्रतिशत हिस्सा), अमरीका (12.2 प्रतिशत हिस्सा) और अफ्रीका (7.5 प्रतिशत हिस्सा) का स्थान था। देश-वार, 2016-17 में भारत के कुल आयात में 16.0 प्रतिशत के हिस्से के साथ चीन सबसे बड़ा स्रोत बना रहा, इसके बाद संयुक्त राज्य अमरीका (5.8 प्रतिशत), संयुक्त अरब अमीरात (5.6 प्रतिशत), सऊदी अरब (5.2 प्रतिशत) और स्विटजरलैंड (4.5 प्रतिशत) का स्थान था। वर्ष 2016-17 में आयात के शीर्ष 5 स्रोतों में, चीन, सऊदी अरब और स्विटजरलैंड से भारत के आयात में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई, जबकि संयुक्त राज्य अमरीका और संयुक्त अरब अमीरात से भारत के आयात में क्रमशः 2.6 प्रतिशत और 10.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

चित्र 9क. भारत के शीर्ष निर्यात गंतव्य ( 2000-01 )



स्रोत: डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों पर आधारित

## चित्र 9ख. भारत के शीर्ष निर्यात गंतव्य (2016-17)



स्रोत: डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों पर आधारित

## व्यापार नीति

### हालिया व्यापार नीतिगत उपाय

6.21 1 अप्रैल, 2015 को प्रारंभ की गई नई विदेश व्यापार नीति (2015-20) निर्यात और आयात के लिए नियमों, प्रक्रियाओं और प्रोत्साहनों को “मेक इन इंडिया”, “डिजिटल इंडिया” और “स्किल्स इंडिया” जैसी अन्य पहलों के साथ जोड़ती है। यह वाणिज्यिक निर्यातों को लाभ देने के लिए पूर्ववर्ती नीति के तहत 5 भिन्न-भिन्न प्रोत्साहन योजनाओं को एक एकल स्कीम नामतः भारत से वाणिज्यिक निर्यात योजना (एमईआईएस) में समेकित करती है। सेवा क्षेत्र के लिए, भारत से सेवा प्रदत्त योजना को प्रतिस्थापित करके भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस) प्रारम्भ की गई है। आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीसीईए) द्वारा तारीख 18 नवम्बर, 2015 को 1 अप्रैल, 2015 से 5 वर्ष तक के लिए नौभरण के पूर्व और पश्च रुपया निर्यात ऋण संबंधी ब्याज समकरण योजना को भी मंजूरी दी गई थी और 3 वर्ष पश्चात इसका मूल्यांकन किया जाएगा। निर्यात हेतु निर्यात व्यापार अवसरंचना योजना (टीआईईएस) नामक नई योजना भी अनुमोदित की गई जिसे वर्ष 2017-18 से 3 वर्ष के लिए लागू किया जाना है। इसके अतिरिक्त,

विलेखों की संख्या को घटाने, 1 अप्रैल, 2016 से सरल आईईसी (आयातक निर्यातक संहिता) प्रारंभ करने, आईईसी की भौतिक प्रति का निर्गमन समाप्त करने, निर्यात वसूली संबंधी आंकड़े राज्यों के साथ आदान-प्रदान करने तथा राज्यों को अपनी निर्यात रणनीतियां तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करने, जिसके परिणामस्वरूप 17 राज्य अपनी निर्यात संबंधी रणनीतियां तैयार कर रहे हैं, आयात-निर्यात प्रपत्रों को सरल बनाने, आदि जैसे अनेक व्यापार सुगमता संबंधी उपाय भी किए गए हैं।

6.22 एफटीपी 2015-20 की मध्यावधि समीक्षा की कवायद शुरू कर दी गई है और समीक्षा की गई एफटीपी की शीघ्र ही घोषणा होने की संभावना है। जबकि समीक्षा संबंधी यह कवायद खासकर हालिया अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों के दृष्टिगत महत्वपूर्ण है, न केवल समीक्षा के लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है अपितु भारत के निर्यात की गति में भी तेजी लाए जाने की आवश्यकता है ताकि 2016 में इसका सम्मानजनक हिस्सा विश्व निर्यात के मौजूदा 1.7 प्रतिशत से बढ़कर कम से कम 5 प्रतिशत तक पहुंच जाए, जो चीन के 13.2 प्रतिशत की तुलना में अत्यधिक कम है (बॉक्स 2 देखें)।



## बॉक्स 2. भारत के वाणिज्यिक निर्यात को पुनः प्रोत्साहित करना तथा गति में तेजी लाना: नीतिगत सुधार

विश्व निर्यात के 5 प्रतिशत का सम्मानजनक हिस्सा प्राप्त करने के लिए, यह अनुमान लगाते हुए कि वैश्विक वृद्धि 1.5 प्रतिशत के सीएजीआर (2010-15) में निरंतर बनी रहती है कम से कम 5 वर्ष (2017-21) तक भारत की निर्यात वृद्धि दर (सीएजीआर) लगभग 26.5 प्रतिशत रहनी होगी। इसके लिए विशिष्ट उपायों के साथ-साथ कुछ प्रमुख रणनीतियां और सुधार आवश्यक हैं।

### प्रमुख रणनीतियां और नीतिगत सुधार

- केवल आपूर्ति आधारित रणनीति के बजाय मांग आधारित निर्यात समूह विविधकरण क्योंकि विश्व के शीर्ष आयातकों में 4 अंकीय स्तर की वस्तुओं का स्थान और विश्व को इन वस्तुओं के निर्यात के मामले में भारत का स्थान 2015 में संख्याओं की दृष्टि से 4 अंकीय स्तर की विश्व की शीर्ष 100 आयात वस्तुओं में इन मदों में भारत के 96.5 प्रतिशत के निर्यात और 6 अंकीय स्तर पर 83.2 प्रतिशत के निर्यात में अत्यधिक अंतर दिखाई देता है, जो मूल्य की दृष्टि से विश्व के 100 शीर्ष आयातकों का केवल 1.6 प्रतिशत बैठता है।
- वर्ष 2015-16 में वसूल किए गए प्रशुल्कों (बीसीडी) के रूप में यौक्तिकीकरण प्रशुल्क 2.8 प्रतिशत की दर पर अत्यधिक कम है और विभिन्न छूटों के कारण औसतन प्रयुक्त प्रशुल्कों के एक-चौथाई से भी कम है। यदि सकल सीमाशुल्क राजस्व से वापस की हुई राशि और वापस ली गई सीमाशुल्क ड्यूटी घटा दी जाती है तो वसूल किए गए निवल प्रशुल्क (बीसीडी) इससे भी कम हो जाएंगे। यद्यपि अनेक कारणों से प्रशुल्कों की भिन्न-भिन्न दरें नियत की जाती हैं, फिर भी संवेदनशील और महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए उच्च प्रशुल्क बनाए रखते हुए अनेक लाइनों से प्रशुल्कों को चयनात्मक रूप से कम करके औसतन प्रयुक्त प्रशुल्कों को कम करने की गुंजाइश है। इसके परिणामस्वरूप विश्व व्यापार संगठन के बाध्य प्रशुल्कों को भी कम किया जा सकता है जो भारत की विश्व व्यापार संगठन और द्विपक्षीय वार्ताओं में और अधिक सकारात्मक भूमिका निभाने में मददगार हो सकता है।
- निर्यात संवर्धन योजनाओं को सरल और कारगर बनाना क्योंकि जीएसटी के तहत अनेक शुल्कों को आपस में मिला दिया गया है और यदि प्रशुल्कों को वसूल किए गए या वसूल किए जाने के आस-पास वाले स्तरों तक कम कर दिया जाता है तो कुछ निर्यात संवर्धन योजनाएं चरणबद्ध तरीके से समाप्त की जा सकती हैं। प्रशुल्क वापसी की संशोधित दरें भी कम की जा सकती हैं। इससे बचे राजस्व का निर्यात विपणन प्रयासों के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- विश्व श्रेणी की निर्यात अवसंरचना और विशेषकर पत्तन से संबंधित संभार तंत्र का युद्ध स्तर पर विकास करना।
- एफडीआई से संबद्ध और मूल्य वर्धित निर्यात, खासकर उच्च-तकनीक के निर्यात चीन और कुछ अन्य आसियान देशों की तरह हों।
- ब्रिक्स और आसियान देशों के साथ, जहां भारत प्रतिस्पर्धात्मक लाभ की स्थिति में है, सक्रियता से संबंध का विस्तार करते हुए कुछ बड़े देशों के साथ उपयोगी मुक्त व्यापार करार/व्यापक आर्थिक सहयोग करार करना।
- राष्ट्रीय निर्यातक प्राथमिकता क्षेत्रक तथा राज्यों को निधियों के अंतरण को राज्यों के निर्यात प्रयत्न के साथ जोड़ते हुए निर्यात में राज्यों की अधिक से अधिक भागीदारी।
- एक स्पष्ट कृषि-व्यापार नीति तैयार करना।

मुख्य कार्यनीतियों के अलावा, व्यापार नीति से संबंधित जटिल मसले और क्षेत्रक विशिष्ट मसले जैसे गैर-व्यस्ततम घंटों के लिए निम्न दरों सहित प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर बिजली उपलब्ध कराना जिससे कपड़ा निर्यात की स्थिति में काफी सुधार हो सकता है; और हार्डवेयर-सॉफ्टवेयर संयोजन तथा सुस्थापित मूल्य श्रृंखला के साथ एक सुदृढ़ विनिर्माण आधार का निर्माण करने के लिए असेम्बलिंग से हटने सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर निर्यात को उच्च गति प्रदान करना।

स्रोत: डॉ॰ आर॰ सतीश, विजय कुमार, एस॰एस॰ सिंह, आर॰के॰ शर्मा के साथ डॉ॰ एच॰ए॰सी॰ प्रसाद: "रिवाइजिंग एंड एक्सलेरेटिंग इंडियाज एक्सपोर्ट्स: पॉलिसी इश्यूज एंड सजेशन्स" वर्किंग-पेपर नं॰ 01/2017-डीईए, जनवरी, 2017।

## प्रतिपाटन (एंटी डंपिंग) उपाय

6.23 2015 में, सभी देशों द्वारा 230 प्रतिपाटन जांचें प्रारंभ की गईं जिनमें अमरीका ने भारत से अधिक लगभग 42 जांचें प्रारंभ कीं (सारणी 7)। तथापि, 2016 में, भारत जी-20 सदस्यों द्वारा प्रारंभ की गई कुल 228 प्रतिपाटन जांचों में से 69 जांचें प्रारंभ करते हुए इन जांचों को प्रारंभ करने वाला सर्वोच्च देश बन गया है, इसके बाद अमरीका (37) और आस्ट्रेलिया (25) का स्थान है (विश्व व्यापार संगठन, 2017)।

6.24 वैश्विक मंदी के समय से, पाटन से संबंधित शिकायतें बढ़ती रही हैं। भारत, देश में मालों के पाटन के

प्रथम दृष्टया साक्ष्य पर घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदनों, घरेलू उद्योग को हुई क्षति और पाटन और क्षति के बीच कार्यकारण संबंध के आधार पर प्रतिपाटन जांचें प्रारंभ करता है। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान, भारत ने 44 प्रतिपाटन जांचें प्रारंभ कीं और 5 प्रतिपाटन जांचों में प्रारंभिक निष्कर्ष, 28 प्रतिपाटन जांचों में अंतिम निष्कर्ष तथा प्रतिपाटन शुल्क जांच के एक प्रति-उपाय में अंतिम निष्कर्ष जारी किए। जो प्रमुख उत्पाद भारत में पाटित कर दिए गए पाए गए हैं और जिनके संबंध में प्रतिपाटन शुल्क लगाया गया है, वे रसायन और पेट्रो-रसायन, इस्पात और अन्य धातुओं के उत्पादों, रेशम और धागा तथा उपभोक्ता



## सारणी 7. प्रतिपाटन उपायों के कुछ प्रमुख उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रारंभ की गई जांचें

देश	भारत	यूएसए	ईयू	ब्राजील	अर्जेंटीना	ऑस्ट्रेलिया	चीन	सभी देश अन्य सहित
2009	31	20	15	9	28	9	17	217
2010	41	3	15	37	14	7	8	173
2011	19	15	17	16	7	18	5	165
2012	21	11	13	47	12	12	9	208
2013	29	39	4	54	19	20	11	287
2014	38	19	14	35	6	22	7	236
2015	30	42	12	23	6	10	11	230
2016	69	37	14	11	25	17	5	145*
1995-2016*	818	593	485	396	328	310	231	5132

स्रोत: विश्व व्यापार संगठन

टिप्पणी: \*30 जून, 2016 तक

मालों के उत्पादों के समूह के अंतर्गत आते हैं। इन जांचों में जुटे देशों में चीन, यूरोपीय संघ, कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, रूस, जापान, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान, थाइलैंड, टर्की, सऊदी अरब, चीनी ताइपेई और

अमरीका शामिल हैं। जिन देशों और उत्पादों के संबंध में भारत द्वारा हाल ही में कुछ प्रतिपाटन जांचें प्रारंभ की गई हैं उनका ब्यौरा सारणी 8 में दिया गया है।

## सारणी 8. 2015-16 से प्रारम्भ की गई प्रतिपाटन जांचें- शामिल देश और उत्पाद

वर्ष	प्रमुख देश	लक्षित प्रमुख मर्दे	प्रतिपाटन जांचों का प्रारम्भ करना	अंतिम निष्कर्ष/ समापन
2015-16	चीन पी आर (23), कोरिया आर पी (5) चीनी ताइपेई (7), थाइलैंड (8), इंडोनेशिया (4), अमरीका (3), रूस (4), मलेशिया (3), वियतनाम (3), पाकिस्तान (3), ईरान (5)	रसायन, पेट्रो रसायन, रेशम और धागा तथा इस्पात निर्मित उत्पाद	36	46
2016-17	चीन पी आर (37), यूरोपीय संघ (5) कोरिया आर पी (5) चीनी ताइपेई (5), थाइलैंड (3), इंडोनेशिया (7), जापान (7) अमरीका (0), रूस (4), मलेशिया (4), ईरान (3), सऊदी अरब (2)	रसायन, पेट्रो रसायन, रेशम और धागा तथा इस्पात निर्मित उत्पाद	44	29
2017-18*	चीन पी आर (8), यूरोपीय संघ (2) कोरिया आर पी (1) चीनी ताइपेई (1), थाइलैंड (2), सिंगापुर (1), इंडोनेशिया (2), अमरीका (1), मलेशिया (1), वियतनाम, टर्की, संयुक्त अरब अमीरात (1), पाकिस्तान (1), हांगकांग, ईरान (1), सऊदी अरब (2)	रसायन, पेट्रो रसायन, रेशम और धागा तथा इस्पात निर्मित उत्पाद	10	11
	जोड़		281	276

स्रोत: प्रतिपाटन तथा तत्संबंधित शुल्क महानिदेशालय

टिप्पणी: 2017-18\* (अर्थात् 30.06.2017 तक), ( ) प्रारम्भ की संख्या

16.25 12 अप्रैल, 2016 को, भारत ने चीन में उत्पन्न कतिपय हॉट-रोल्ड और कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील प्लेट उत्पादों के आयातों से संबंधित प्रतिकारी शुल्क जांच आरंभ की। इसने अपनी जांच क्रियाविधि को आईएसओ 9001: 2015 अनुपालक बनाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है।

## बहुपक्षीय और द्विपक्षीय/क्षेत्रीय वार्ताएं और भारत

6.26 प्रशांत क्षेत्र-पार भागीदारी (टीपीपी) से अमरीका के हटने, संरक्षणवाद के बढ़ने और अनेक देशों में विश्व व्यापार संगठन वार्ता की ओर वापस लौटने के विचार के परिणामस्वरूप विश्व व्यापार संगठन में समान वार्ताओं के लिए अवसर की गुंजाइश बन गयी है। डब्ल्यूटीओ का ग्यारहवां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमसी 11) ब्यूनस आयरस, अर्जेन्टीना में दिसम्बर, 2017 में आयोजित किए जाने को निर्धारित है। डब्ल्यूटीओ में एमसी 11 के निष्कर्ष तथा विभिन्न अनौपचारिक बैठकों में मुख्य वार्ताओं से हटकर व्यापार मंत्रियों के स्तर पर विचार-विमर्श जारी है। इन सभी बैठकों में, भारत ने बाली और नैरोबी में पिछले डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों में मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णय, विशेषकर विकासशील देशों के लिए खाद्य सुरक्षा के प्रयोजनार्थ सार्वजनिक अंशधारिता, और कृषि संबंधी विशेष सुरक्षा तंत्र लागू करने से संबंधित मुद्दे संबंधी निर्णयों को कार्यान्वित करने की जरूरत पर जोर दिया। भारत ने डब्ल्यूटीओ में कोई मुख्य वार्ता करने से रह गए विकासशील देशों के लिए विशेष और भिन्न सुविधा सहित दोहा कार्यसूची में अन्य मसलों से संबंधित निष्कर्षों की जरूरत पर भी बल दिया है।

6.27 डब्ल्यूटीओ व्यापार सुविधा करार, व्यापार लागत घटाने की अंतरराष्ट्रीय कार्यप्रणाली सृजित करके एक जरूरी मील के पत्थर का प्रतीक है। इस करार का उद्देश्य “भारत की व्यवसाय करने की आसानी” वाली पहल के अनुरूप है। भारत के विचार में, खासकर विकासशील देशों के लिए व्यापार सुविधा जरूरी है। व्यापार संव्यवहार की लागत में मामूली कमी से भी विकसित और विकासशील दोनों देशों के व्यापार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। भारत

ने, अपनी प्रतिबद्धताओं के अनुसार, अपनी श्रेणी ‘क’ प्रतिबद्धताएं मार्च 2016 में अधिसूचित कीं और बाद में व्यापार सुविधा करार (टीएफए) का अनुसमर्थन अप्रैल, 2016 में किया। टीएफए के तहत दिए गए कुल उपबंधों में से तकरीबन 70 प्रतिशत उपबंध ‘क’ श्रेणी के रूप में अधिसूचित किए गए हैं। शेष उपबंध श्रेणी “ख” के तहत वर्गीकृत किए गए हैं। इन्हें 5 वर्ष की संक्रमण अवधि के पश्चात कार्यान्वित किया जाएगा। देश में टीएफ के उपबंधों के समन्वयन और कार्यान्वयन दोनों को सुकर बनाने के लिए राष्ट्रीय व्यापार सुविधा समिति (एनसीटीएफ) गठित की गई है। व्यापार में बाधाओं को और आसानी से दूर करने के लिए विशिष्ट कार्यकलापों वाली कार्ययोजना तैयार की गई है। पूरे विश्व के लिए सेवाओं में व्यापार के बढ़ते महत्व को स्वीकार करते हुए भारत ने मालविशिष्ट व्यापार सुविधा करार (टीएफए) के समकक्ष के रूप में, डब्ल्यूटीओ में व्यापार सुविधा सेवा (टीएफएस) करार पर चर्चा करने की पहल की है (अध्याय 9 देखें)।

भारत अनेक द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग करारों में भी शामिल रहा है। भारत के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय करारों से संबंधित हालिया घटनाक्रम बॉक्स 3 में दिए गए हैं।

## विदेशी मुद्रा भंडार

6.28 चालू खाता घाटे में चल रही मुख्य अर्थव्यवस्थाओं में, भारत ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश है। विदेशी मुद्रा भंडार का स्तर बीओपी आधार पर आरक्षित निधि में बदलाव और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित आस्तियों के मूल्यांकन में परिवर्तनों के कारण परिवर्तित हो सकता है। 2016-17 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बीओपी आधार पर (अर्थात् मूल्यांकन प्रभाव छोड़कर) 21.6 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ गया, जबकि 2015-16 में सांकेतिक दृष्टि से (अर्थात् मूल्यांकन प्रभाव सहित) इस भंडार में 18.5 बिलियन अमरीकी डालर की बढ़त की अपेक्षा 9.8 बिलियन अमरीकी डालर तक की वृद्धि हुई। मुख्य मुद्राओं के मुकाबले अमरीकी डालर की मूल्य वृद्धि को प्रधानतः प्रतिबिंबित करते हुए मूल्यहास 2015-16 में 0.6 बिलियन

### बाक्स 3. भारत के कुछ हालिया द्विपक्षीय/क्षेत्रीय सहयोग करारों की स्थिति

- **आसियान+एफटीए के 6 साझेदारों ( आस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड ) के बीच आरसीईपी करार:** नवंबर, 2012 में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं द्वारा की गई घोषणा के आधार पर, आसियान के 10 सदस्य देशों और इसके 6 साझेदारों के बीच क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) करार पर वार्ता मई, 2013 में आरंभ हुई। तीसरा इंटरनेशनल आरसीईपी मिनिस्टेरियल हनोई में 21 से 22 मई, 2017 तक संपन्न हुआ। भारत आरसीईपी के 19वें दौर के वार्ता की मेजबानी हैदराबाद में 18-28 जुलाई, 2017 तक करेगा। वार्ताओं में माल-व्यापार, सेवा, निवेश, बौद्धिक संपदा, आर्थिक और तकनीकी सहयोग, प्रतिस्पर्धा और विधिक तथा संस्थागत मसले शामिल हैं।
- **भारत श्रीलंका ईटीसीए:** भारत और श्रीलंका के पास 1998 में हस्ताक्षरित और मार्च 2000 में प्रवृत्त मुक्त व्यापार करार विद्यमान है जिसमें माल व्यापार भी शामिल है। दिसंबर, 2015 में, भारत और श्रीलंका 'आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग करार (ईटीसीए)' नामक नये व्यापक करार के लिए वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। करार के कार्यक्षेत्रों में माल-व्यापार के अलावा सेवा-व्यापार, निवेश मसले और प्रौद्योगिकी, सीमाशुल्क, मानक आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग शामिल हैं। अब तक वार्ता के चार और आयोजित किए जा चुके हैं, हालिया दौर 24-26 अप्रैल 2016 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।
- **भारत ईयूबीटीआईए:** माल, सेवा, निवेश, स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपाय, व्यापार में तकनीकी अवरोध, व्यापार सुविधा तथा सीमाशुल्क सहयोग, प्रतिस्पर्धा, आईपीआर और जीआईएस, आदि के क्षेत्रों में वार्ताएं 28 जून, 2007 को प्रारंभ हुईं। ये वार्ताएं जनवरी, फरवरी, जुलाई और नवंबर, 2016 में जायजा लेने वाली 4 बैठकों में दुबारा शुरू हुईं।
- **भारत-थाइलैंड सीईपीए:** व्यापार वार्ता समिति का 30वां दौर नई दिल्ली में 13-14 जुलाई, 2016 को संपन्न हुआ। 82 मदों से संबंधित अर्ली हारवेस्ट स्कीम लागू कर दी गई है।
- **भारत-कोरिया सीईपीए समीक्षा:** नई दिल्ली में 18 जून, 2016 को आयोजित मंत्रिस्तरीय संयुक्त समिति की बैठक के दौरान, दोनों पक्षकारों ने भारत-कोरिया सीईपीए के अद्यतनीकरण के लिए वार्ता शुरू करने की घोषणा की। भारत-कोरिया सीईपीए के अद्यतनीकरण वार्ताओं के दो दौर अब तक हो चुके हैं। वार्ता का दूसरा दौर नई दिल्ली में 13-14 फरवरी, 2017 को संपन्न हुआ था।
- **भारत-ईएईयूएफटीए:** संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन समूह (जेएफएसजी) की रिपोर्ट को भारत और ईएईयू (यूरेशियाई आर्थिक संघ) द्वारा सितंबर, 2016 में अंतिम रूप दिया गया। भारत को एफटीए वार्ताएं आरंभ करने के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त हो गया है। तथापि, ईएईयू अभी सक्षम प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

स्रोत: वाणिज्य विभाग

अमरीकी डालर के लाभ की तुलना में 2016-17 में 11.8 बिलियन अमरीकी डालर बैठता था (सारणी 9)। मार्च 2016 की तुलना (सांकेतिक दृष्टि से) में आरक्षित निधि में 9.8 बिलियन अमरीकी डालर की बढ़त के साथ आयात के लिए आरक्षित निधि कवर भी मार्चान्त 2016 में 10.9 माह से मार्चान्त 2017 में बढ़कर 11.3 माह हो गया।

6.29 भारतीय रिजर्व बैंक, बाजार के हालात को व्यवस्थित बनाए रखने तथा उसमें अत्यधिक घट-बढ़ को नियंत्रित करने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार के हाजिर बाजार और वायदा बाजार खंडों दोनों में हस्तक्षेप करता है। यह विदेशी मुद्रा बाजार में विदेशी मुद्रा का क्रय-विक्रय करता है जिससे कि मुख्य रूप से मांग या आपूर्ति की अपवृद्धि में बुनियादी संतुलन स्थापित किया जा सके। पिछले कुछ महीनों में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई वायदा खरीदें हाजिर खरीदों से अधिक थीं। हस्तक्षेप से संबंधित साधन (हाजिर और वायदा) का विकल्प,

हस्तक्षेप के उद्देश्य और विदेशी मुद्रा बाजार में व्याप्त स्थिति पर निर्भर करता है। हाजिर और वायदा बाजारों के बीच हालिया कार्रवाई संबंधी कार्यों के वितरण से संबंधित निर्णय, रुपया नकदी, विद्यमान बकाया वायदा आस्ति/देयताओं की वायदा प्रीमियम स्थिति पर प्रभाव, आदि जैसे दिनानुदिन आधार से संबंधित कारक समूह द्वारा दिशानिर्देशित होते रहते हैं। 2014-16 के दौरान जब कभी हस्तक्षेप क्रय के संबंध में किया गया, तब एक सचेत प्रयत्न वायदा बाजार में समुचित मात्रा में क्रय करने के लिए किया गया ताकि एफसीएनआर(बी) और ओवरसीज विदेशी मुद्रा उधार (ओएफसीबी) विनिमय की परिपक्वता के कारण निर्धारित बहिर्वाह को कवर किया जा सके।

6.30 भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, जनवरी से मार्च, 2017 तक हस्तक्षेप 18 मिलियन अमरीकी डालर था, जिसमें से लगभग 5

## सारणी 9. विदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तन का 'सार' ( बिलियन अमरीकी डालर )

वर्ष	वित्त वर्ष के अंत ( मार्चांत ) में विदेशी मुद्रा भंडार	आरक्षित निधि में कुल वृद्धि ( + )/ कमी ( - )	बीओपी आधार पर आरक्षित निधि में वृद्धि/कमी	मूल्यांकन प्रभाव के कारण आरक्षित निधि में वृद्धि/कमी
2007-08	309.7	110.5	92.2	18.3
2008-09	252.0	-57.7	-20.1	-37.6
2009-10	279.1	27.1	13.4	13.7
2010-11	304.8	25.8	13.1	12.6
2011-12	294.4	-10.4	-12.8	2.4
2012-13	292.0	-2.4	3.8	-6.2
2013-14	304.2	12.2	15.5	-3.3
2014-15	341.6	37.4	61.4	-24
2015-16	360.2	18.5	17.9	0.6
2016-17	370.0	9.8	21.6	-11.8

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

बिलियन अमरीकी डालर हाजिर बाजार में और शेष 13 बिलियन अमरीकी डालर वायदा बाजार के जरिए प्राप्त हुआ। वायदा खरीदों के रूप में अधिकतर हस्तक्षेप इस तथ्य के कारण किया गया कि विमुद्रीकरण के परिणामस्वरूप बैंकिंग तंत्र में बेशी नकदी आ गई थी और किसी अतिरिक्त हाजिर-बाजार हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप इस तंत्र की बेशी नकदी में इजाफा ही हो सकता था।

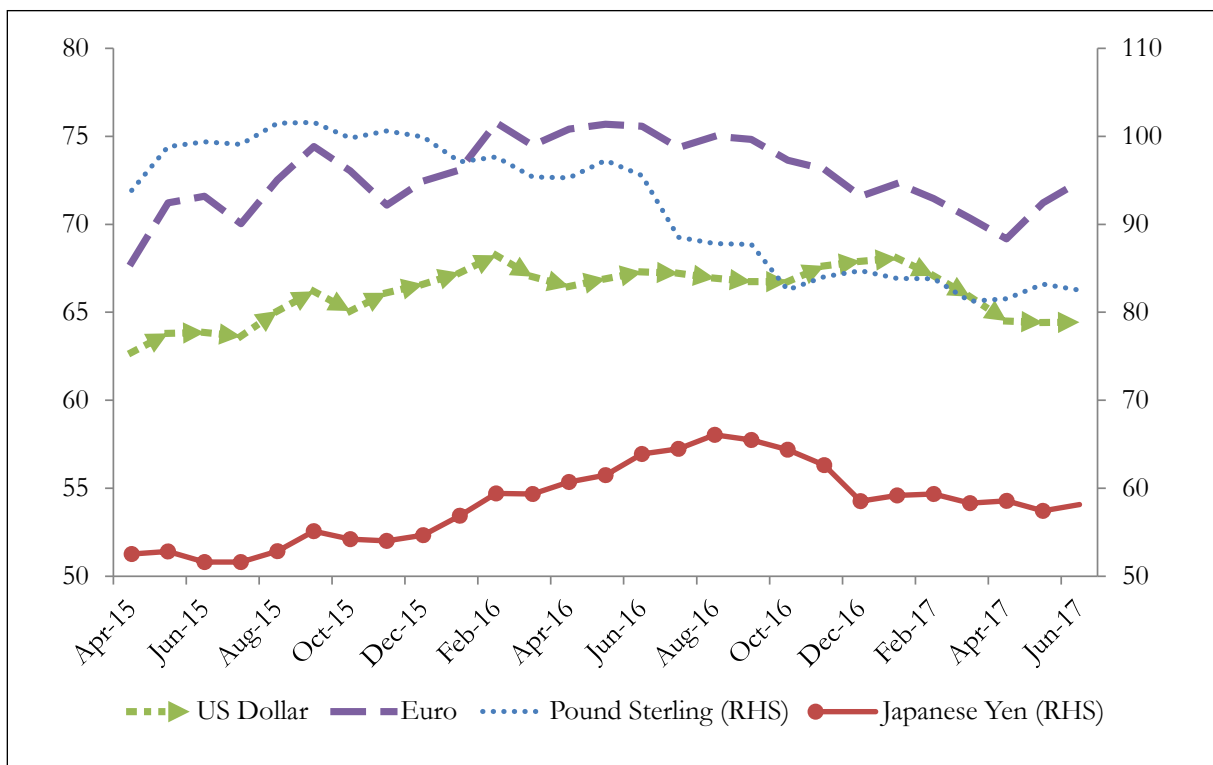
### विनिमय दर

6.31 रुपये की औसत वार्षिक विनिमय दर का मूल्य 2015-16 में 65.5 ₹ प्रति अमरीकी डालर से घटकर 2016-17 में 67.1 रुपया प्रति अमरीकी डालर रह गया। 2016-17 में, अमरीकी डालर, यूरो और जापानी येन के मुकाबले रुपए का अवमूल्यन क्रमशः 2.4 प्रतिशत, 1.8 प्रतिशत और 12.0 प्रतिशत हुआ, जबकि इसमें पाउंड स्टर्लिंग के मुकाबले 12.6 प्रतिशत तक अधिमूल्यन हुआ। अमरीकी डालर के मुकाबले रुपये की औसत मासिक विनिमय दर में नवंबर 2016 से जनवरी 2017 तक लगातार अवमूल्यन के बाद, फरवरी से जून 2017 तक लगातार अधिमूल्यन हुआ है, जबकि पाउंड स्टर्लिंग, यूरो

और जापानी येन के मामले में मासिक रूप से भिन्नता रही है (चित्र 10)

6.32 2016-17 में कई अन्य ईएमई-मुद्राओं से रुपए ने बेहतर प्रदर्शन किया। जहां वार्षिक औसत आधार पर, यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का 2.4 प्रतिशत तक अवमूल्यन हुआ, वहीं चीनी युआन (6.0 प्रतिशत), अर्जेन्टिनियाई पेसो (29.1 प्रतिशत), मलेशियाई रिंगिट (3.7 प्रतिशत), मेक्सिको पेसो (13.5 प्रतिशत) और टर्की लीरा (11.3 प्रतिशत) की तुलना में इसका अधिक अवमूल्यन हुआ। यूएस के राष्ट्रपति के चुनाव के बाद आए नतीजों और नवंबर, 2016 में घरेलू रूप से घोषित विमुद्रीकरण अभियान के चलते अनिश्चितता के कारण भारतीय रुपए पर गिरावट का स्पष्ट रूप से दबाव था। परंतु, रुपए में दिसंबर, 2016 से तेजी से सुधार आया है, वैश्विक जोखिम अनिच्छा कम होने के चलते विदेशी पोर्टफोलियो प्रवाह सकारात्मक हो जाने और सुधारों पर केन्द्रित केंद्रीय बजट तथा राज्य चुनावों के निर्णायक परिणामों के कारण फरवरी, 2017 से आगे इसमें और भी सुधार हुआ है। 2017-18 (अप्रैल-जून) के दौरान,

चित्र 10. अमरीकी डालर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग और जापानी येन की तुलना में रुपये में घट-बढ़



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

2016-17 के वार्षिक औसत के मुकाबले अमरीकी डॉलर की तुलना में रुपए में 4.0 प्रतिशत तक सुधार हुआ। जबकि अमरीकी डॉलर के मुकाबले रूसी रूबल में 10.3 प्रतिशत तक और दक्षिण अफ्रीकी रैंड में 6.2 प्रतिशत तक का सुधार हुआ, चीनी युआन और मलेशियाई रिंगिट में अमरीकी डॉलर के मुकाबले क्रमशः 1.9 प्रतिशत और 2.9 प्रतिशत तक की गिरावट आई।

6.33 विनिमय दर के क्षेत्र में एक हालिया गतिविधि यह है कि संयुक्त राज्य अमरीका ने अनुचित ढंग से व्यापार करने पर रोक लगाने के लिए अनुचित मुद्राओं संबंधी नीतियां लागू की हैं और मुद्रा में हेर-फेर करने वालों पर नज़र भी रख रहा है। यूएस ट्रेजरी का ध्यान अमरीका के साथ कारोबार कर रहे 12 सबसे बड़े भागीदारों पर है, जिनकी हिस्सेदारी वस्तुओं में अमरीकी कारोबार की लगभग 70 प्रतिशत बैठती है। इसमें भारत भी शामिल है। लेकिन, भारत निगरानी सूची में नहीं है (बाक्स 4)।

6.34 2016-17 के दौरान, औसतन (वर्षानुवर्ष आधार पर), यूएस डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में 2.4 प्रतिशत तक का अवमूल्यन हुआ, 6 और 36 मुद्राओं के समूह के प्रति सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) के अनुसार, रुपया क्रमशः 0.5 प्रतिशत और 0.1 प्रतिशत कमजोर हुआ। तथापि, 2016-17 में, 6 और 36 मुद्राओं के समूह की तुलना में वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) के अनुसार, रुपया क्रमशः 2.7 प्रतिशत और 2.2 प्रतिशत मजबूत हुआ। 6-मुद्रा और 36-मुद्रा आरईईआर (कारोबार-आधारित; आधार वर्ष: 2004-05 = 100) में मार्च, 2016 के मुकाबले मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार क्रमशः 7.6 प्रतिशत और 6.3 प्रतिशत तक की तेजी आई। जबकि ईएमई में सर्वाधिक स्थाई मुद्राओं में रुपया शामिल रहा है, आरईईआर में वृद्धि यह इंगित करती है कि भारत के निर्यातों की प्रतिस्पर्धा में मामूली कमी आई है (चित्र 11)।

**बाक्स 4. यूएस द्वारा मुद्रा में हेरा-फेरी करने वालों की निगरानी**

मुद्रा में हेर-फेर करने वाले देशों पर नज़र रखने के लिए, यूएस ट्रेजरी ने ट्रेड फ़ैसिलिटेशन एंड ट्रेड एंफोर्समेंट एक्ट, 2015 में दिए गए तीन मानदंडों के लिए प्रारंभिक सीमाएं निर्धारित की हैं और नए प्रशासन के अधीन यूएस ट्रेजरी ने विदेशी मुद्रा में हेर-फेर करने वालों का वर्गीकरण करने वाले नियमों के अनुसार यथास्थिति बनाए रखी है। पहला मानदंड यूनाइटेड स्टेट्स के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय कारोबार अधिशेष है (कम से कम 20 बिलियन अमरीकी डॉलर) जबकि दूसरा मानदंड जीडीपी के प्रतिशत के अनुसार देश का चालू खाता शेष है (जीडीपी का कम से कम 3 प्रतिशत) और तीसरा मानदंड विदेशी मुद्रा बाजार में निरन्तर एक-पक्षीय हस्तक्षेप तथा 12 महीनों की अवधि के मुकाबले निवल 8 महीनों में किसी अर्थव्यवस्था की कुल जीडीपी का कम से कम 2 प्रतिशत है (यूएस ट्रेजरी रिपोर्ट अप्रैल 2017)। 2017 की ट्रेजरी रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए सभी तीनों मानदंडों के पैरामीटर को कोई भी मुख्य कारोबारी भागीदारी पूरा नहीं करता है। तथापि, 2015 के अधिनियम में तीन में से दो मानदंडों को पूरा नहीं कर रही अर्थव्यवस्था को निगरानी सूची में रखा जाएगा। यद्यपि चीन इन तीन में से दो मानदंड पूरे नहीं करता, तथापि यूएस, ट्रेजरी ने यह कहते हुए उसे शर्तों में ढील दे दी कि संपूर्ण यूएस कारोबार घाटे के बड़े और गैर-आनुपातिक हिस्सेदार देशों को निगरानी सूची में रखा जाएगा। अब चीन, जापान, कोरिया, ताइवान, जर्मनी और स्विटजरलैंड जैसे देशों को 2017 में निगरानी सूची में रखा गया है और ये कम-से-कम दो लगातार रिपोर्टों तक सूची में बने रहेंगे। भारत निगरानी सूची में नहीं है क्योंकि यह कारोबार अधिशेष के केवल पहले मानदंड को पूरा करता है, जो 24.3 बिलियन अमरीकी डालर बैठता है जोकि 20 बिलियन अमरीकी डालर की प्रारंभिक सीमा से मामूली-सा अधिक है (सारणी 10)।

**सारणी 10. यूएस द्वारा प्रमुख विदेशी व्यापार भागीदारों के मूल्यांकन का मानदंड**

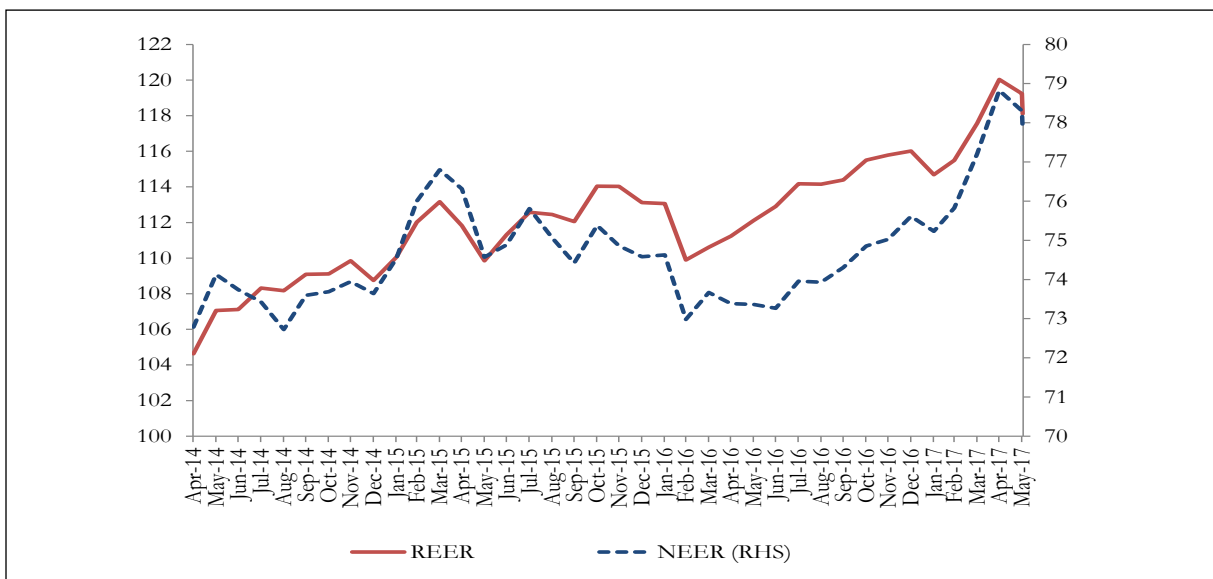
देश	द्विपक्षीय वस्तु घाटा ( बिलियन अमरीकी डॉलर, अनुगामी चौथी तिमाही )	चालू खाता			विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप		
		( जीडीपी का शेष %, अनुगामी चौथी तिमाही )	शेष में 3 वर्षीय परिवर्तन ( जीडीपी का % )	शेष ( बिलियन अमरीकी डॉलर, अनुगामी चौथी तिमाही )	निवल फोरेक्स क्रय ( जीडीपी का % )	निवल फोरेक्स क्रय ( बिलियन अमरीकी डॉलर )	निवल फोरेक्स क्रय 12 माह के 8 माह
चीन	347.0	1.8	0.2	196	-3.9	-435	नहीं
जापान	68.9	3.8	2.9	186	0.0	0	नहीं
जर्मनी	64.9	8.3	1.5	286	-	-	नहीं
मैक्सिको	63.2	-2.7	-0.2	-28	-0.5	-6	नहीं
इटली	28.5	2.8	1.8	51	-	-	नहीं
कोरिया	27.7	7.0	0.8	99	-0.5	-7	नहीं
भारत	24.3	-0.5	2.1	-11	0.4	10	नहीं
फ्रांस	15.8	-1.2	-0.3	-30	-	-	नहीं
स्विटजरलैंड	13.7	10.7	-0.8	71	10.0	66	हां
ताइवान	13.3	13.4	3.4	71	1.8	10	हां
कनाडा	11.2	-3.3	-0.1	-51	0.0	0	नहीं
यूनाइटेड किंगडम	-1.1	-5.1	-1.1	-138	0.0	0	नहीं
मेमो: यूरो क्षेत्र	125.7	3.4	1.2	403	0.0	0	नहीं

स्रोत: कांग्रेस को रिपोर्ट, संयुक्त राज्य के प्रमुख व्यापार भागीदारों की विदेशी मुद्रा नीतियां, अप्रैल, 2017, यूएस ट्रेजरी विभाग।

टिप्पणी: निगरानी मानदंड :

- (क) यूएस के साथ द्विपक्षीय कारोबार अधिशेष (कम से कम 20 बिलियन डॉलर)
- (ख) चालू खाता शेष (जीडीपी का कम से कम 3 प्रतिशत)
- (ग) विदेशी मुद्रा बाजार में निरन्तर एक-पक्षीय हस्तक्षेप तथा 12 महीनों की अवधि के मुकाबले निवल 8 महीनों में किसी अर्थव्यवस्था की कुल जीडीपी का कम से कम 2 प्रतिशत

चित्र 11. एनईईआर और आरईईआर (व्यापार आधारित-36 मुद्राएं) के सूचकांकों में उतार-चढ़ाव  
2004-05=100



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

## विदेशी ऋण

6.35 मार्चान्त 2017 में भारत का सकल विदेशी ऋण स्टॉक 471.9 बिलियन अमरीकी डालर था, जिसमें मार्चान्त 2016 की तुलना में 13.1 बिलियन अमरीकी डालर (2.7 प्रतिशत) की कमी दर्ज हुई। मार्चान्त 2017 में दीर्घावधि विदेशी ऋण 383.9 बिलियन अमरीकी डालर था, जिसमें मार्चान्त 2016 के स्तर की तुलना में 4.4 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई, जबकि 88.0 बिलियन अमरीकी डालर के अल्पावधि ऋण में 5.5 प्रतिशत की

वृद्धि हुई। 2016-17 के दौरान विदेशी ऋण में कमी दीर्घावधि विदेशी ऋण में कमी के चलते आई थी। यह कमी विशिष्ट रूप से एफसीएनआर(बी) जमाओं के मोचन प्रतिबिंबित करने वाली एनआरआई जमाओं में गिरावट (बाक्स 5) तथा वाणिज्यिक उधारों में कमी के कारण आई थी। (बाक्स 5) भारत का विदेशी ऋण परिपक्वता पैटर्न यह दर्शाता है कि मार्चान्त 2017 में कुल विदेशी ऋण में दीर्घावधि उधारों का प्रधान हिस्सा 81.4 प्रतिशत बैठता है (सारणी 11)।

सारणी 11. भारत के विदेशी ऋण की संरचना

(प्रतिशत)

क्र.सं.	घटक	मार्च 2015	मार्च 2016 R	मार्च 2017 P
1	बहुपक्षीय	11.0	11.1	11.5
2	द्विपक्षीय	4.6	4.6	4.9
3	आईएमएफ	1.2	1.2	1.1
4	कारोबार क्रेडिट	2.7	2.2	2.1
5	वाणिज्यिक उधार	38.0	37.3	36.7
6	एनआरआई जमाएं	24.3	26.2	24.8
7	रूपए ऋण	0.3	0.3	0.3
8	दीर्घावधि ऋण (1 से 7)	82.0	82.8	81.4
9	अल्पावधि ऋण	18.0	17.2	18.6
10	कुल विदेशी ऋण	100.0	100.0	100.0

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

टिप्पणी: सं: संशोधित; अ: अनंतिम।

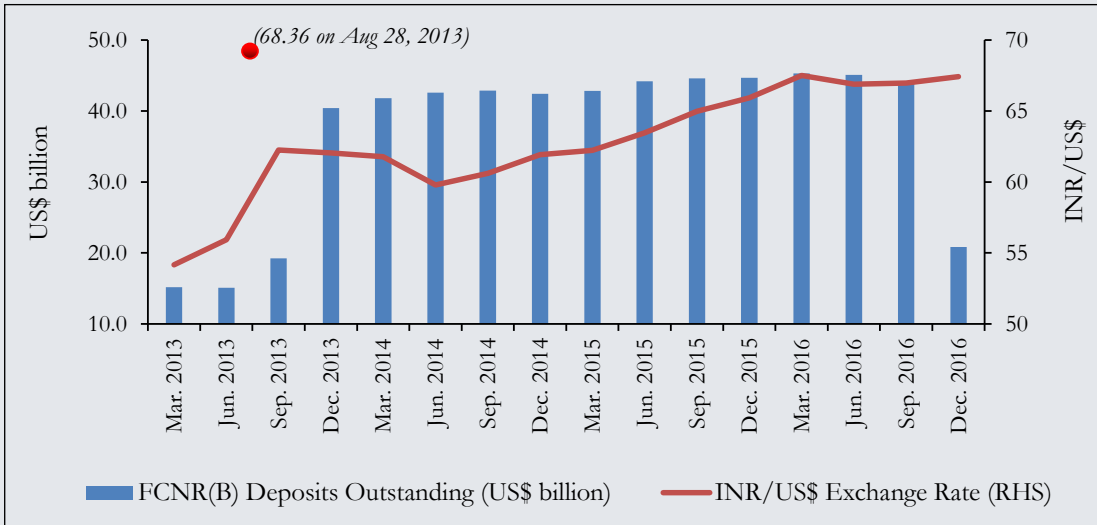


**बॉक्स 5. एफसीएनआर (बी) डालर निधियों का मोचन**

मई 2013 में, मात्रात्मक सुगमता (क्यूई) कटौती का यूएस फेड का पहला संकेत अत्यधिक उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) से शीघ्र और बड़े पूंजी बहिर्वाहों में परिणामी हुआ। इन बहिर्वाहों ने भारत सहित ईएमई की मुद्राओं पर अधोगामी दबाव बढ़ा दिया। क्यूई कटौती के फेड के पहले संकेत से तीन महीने की अवधि में, अमरीकी डालर के मुकाबले भारतीय रुपए की विनिमय दर में लगभग 19 प्रतिशत तक की गिरावट आई और 28 अगस्त, 2013 को यह 68.36 रुपए के सबसे निचले स्तर पर दर्ज की गई।

**एफसीएनआर(बी) जमाओं के लिए अदला-बदली सुविधा:** वैश्विक ब्याज दर चक्र और वित्तीय परिस्थितियों संबंधी अनिश्चितता होने के बावजूद प्रतिरोधकों (बफर्स) के पुनर्निर्माण और विनिमय दर में उतार-चढ़ाव को थामने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने 3.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की नियत लागत पर भारतीय रिजर्व बैंक के साथ नई एफसीएनआर(बी) डालर निधियों की अदला-बदली करने के लिए बैंकों के लिए सीमित अवधि विशेष योजना (04 सितंबर-30 नवंबर, 2013) के अंतर्गत एक अवसर मुहैया कराया और उनकी विदेशी उधार सीमा को बैंकों की अक्षत टायर-1 पूंजी के 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया (भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अदला-बदली के विकल्प सहित)। इसके परिणामस्वरूप अदला-बदली सुविधा के अधीन एफसीएनआर(बी) विंडो और बैंकों के विदेशी उधार दोनों के जरिए) 34.3 बिलियन अमरीकी डालर का पूंजी अंतर्वाह हुआ, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार में पुनर्वृद्धि करने तथा इस प्रकार विदेशी वित्तपोषण की संभावित अपेक्षा को कवर करने और विदेशी मुद्रा बाजार में समन्वित रूप में स्थिरता लाने में सहायता मिली। अदला-बदली सुविधा के दौरान, एफसीएनआर(बी) जमाओं में वृद्धि के कारण, भारत का विदेशी ऋण जून 2013 के अंत में 404.8 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर दिसंबर, 2013 के अंत में 426.9 बिलियन अमरीकी डालर हो गया (चार्ट 1)। जुटाई गई नई एफसीएनआर(बी) डालर निधियों के लिए अदला-बदली की सुविधा तीन वर्षों की न्यूनतम अवधि वाली निधियों के लिए थी। बकाया एफसीएनआर(बी) जमाएं, जो जून, 2013 के अंत में 15 बिलियन अमरीकी डालर थीं, दिसंबर, 2013 के अंत में बढ़कर 40 बिलियन अमरीकी डालर हो गई थीं।

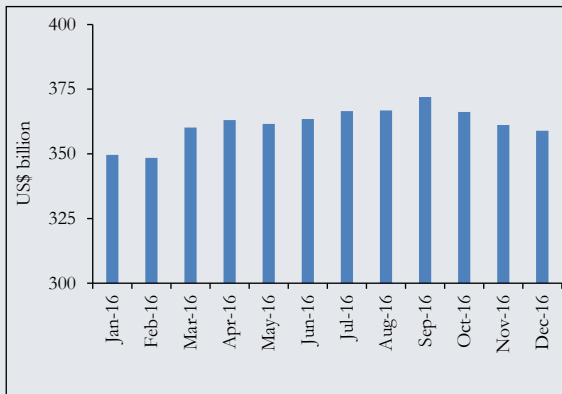
**चार्ट 1. एफसीएनआर(बी) जमा बकाया और अमरीकी डालर के मुकाबले भारतीय रुपए की विनिमय दर**



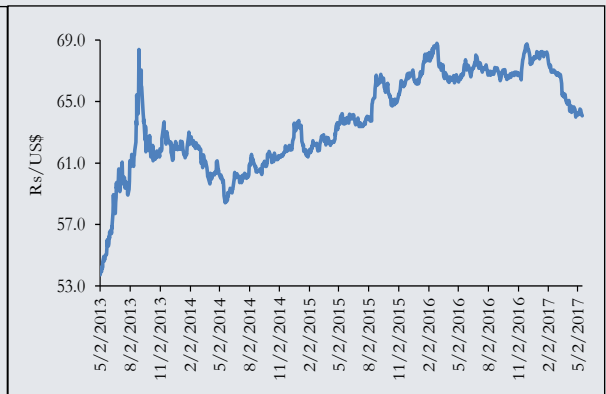
**एफसीएनआर(बी) डालर निधियों का मोचन:** एफसीएनआर(बी) डालर निधियों का मोचन सितंबर-नवंबर, 2016 में शुरू किया गया था। एफसीएनआर(बी) जमाओं के सुविधाजनक मोचन को सुनिश्चित करने के लिए, रिजर्व बैंक ने मुक्त बाजार प्रचालनों (ओएमओ) और वायदा खरीदों के स्पॉट हस्तक्षेप/सुपुर्दगियों के जरिए नकदी प्रावधान फ्रंटलोडिंग किया। 2014-16 के दौरान जब कभी हस्तक्षेप खरीद की ओर किया गया था, तब विदेशी मुद्रा भंडार में तीव्र गिरावट को रोकने और रुपए की नकदी पर प्रभाव को निष्प्रभावी करने के लिए भी एफसीएनआर(बी) और ओएफसीबी (बाहरी विदेशी मुद्रा उधार) अदला-बदली परिपक्वताओं के कारण अनुसूचित बहिर्वाहों को कवर करने के लिए वायदा में क्रय का उचित भाग रखने की ओर सतर्क प्रयास किया गया था। नकदी प्रभाव को ओएमओ क्रय सम्यक् निर्धारण द्वारा भी संभाला गया था। 2014-2015 और 2015-16 में, भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रमशः 54.8 बिलियन अमरीकी डालर और 10.2 बिलियन अमरीकी डालर की राशि की विदेशी आस्तियों की निवल खरीद की थी, ताकि मोचन अवधि के दौरान अनुमानित बहिर्वाह को कवर किया जा सके। बाजार भागीदारों को आश्वस्त करने के लिए और एफसीएनआर(बी) तथा ओएफसीबी अदला-बदली की दीर्घ परिपक्वता के कारण किसी उतार-चढ़ाव को हतोत्साहित करने के लिए, एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि ये अदला-बदलियां वायदा खरीदों द्वारा पर्याप्त रूप से कवर की गई हैं। इसके अलावा, यह सूचना भी दी गई कि भारतीय रिजर्व बैंक चल रही बाजार गतिविधियों पर सक्रिय रूप से नजर रख रहा है और अदला-बदली संव्यवहारों को पूरा करने और रुपए नकदी के सहगामी परिवर्तनों के संबंध में यदि बाजार में कोई उतार-चढ़ाव आता है, तो वह इसे थामने के लिए तैयार है। तथापि, चूंकि वायदा खरीदें और एफसीएनआर(बी) अदला-बदलियां परिपक्वता बैंडों के अनुसार स्टीक रूप से समकालिक नहीं थीं, अतः विदेशी मुद्रा भंडारों में मोचन अवधि के दौरान आरंभ में मामूली कमी

के बाद काफी अभिवृद्धियां देखी गईं। इससे सितंबर-नवंबर, 2016 के दौरान एफसीएनआर(बी) निधियों का सफलतापूर्वक मोचन करने में भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंकिंग प्रणाली को मदद मिली। मोचन के बाद, दिसंबर 2016 के अंत में बकाया एफसीएनआर(बी) जमाएं 21 बिलियन अमरीकी डालर बैठती थीं, जिसके कारण भारत का विदेशी ऋण स्टॉक भी मार्चान्त 2016 के स्तर के मुकाबले दिसंबर 2016 के अंत में गिरकर 29.0 बिलियन अमरीकी डालर (6.0 प्रतिशत) रह गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2016 में पूरे वर्ष सुविधाजनक विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति बनाए रखी (चार्ट 2)। चूंकि मोचन अवधि और यूएस राष्ट्रपति चुनाव परिणाम के बाद की अनिश्चितता और घरेलू रूप से घोषित किए गए विमुद्रीकरण अभियान जैसे अन्य प्रतिकूल आघात भी आंशिक रूप से समकालीन थे, जिसके कारण भारतीय रुपए पर अल्पकालिक अधोगामी दबाव बना रहा। तथापि, भारतीय रुपया दिसंबर, 2016 से तेजी से मजबूत हुआ, जो फरवरी 2017 से आगे और भी मजबूत हो गया, क्योंकि विदेशी पोर्टफोलियो प्रवाह सुधारों के पक्ष में बनाए गए केंद्रीय बजट तथा राज्यों के चुनावों के निर्णायक परिणाम के बाद सकारात्मक हो गया (चार्ट-3)। उपर्युक्त उपायों के साथ चालू खाता घाटे में कमी की स्थिति तथा सुदृढ़ एफडीआई आवक ने एफसीएनआर (बी) निक्षेपों के कारण होने वाले बहिर्वाह की रक्षा करने में मदद की।

चार्ट 2. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार



चार्ट 3. यूएस डॉलर की तुलना में भारतीय रुपए की विनिमय दर



स्रोत: आरबीआई और इनहाऊस अनुसंधान

6.36 भारत की कुल विदेशी ऋण की करेंसी संरचना यह दर्शाती है कि मार्च 2017 के अंत की स्थिति के अनुसार भारत के कुल विदेशी ऋण का 52.1 प्रतिशत का ऋण यूएस डॉलर मूल्यवर्ग के हिसाब में है, इसके बाद भारतीय रुपये (33.6 प्रतिशत), एसडीआर (5.8 प्रतिशत), जापानी येन (4.6 प्रतिशत) तथा यूरो (2.9 प्रतिशत) मूल्य वर्ग के हिसाब में हैं। मार्च 2017 के अंत की स्थिति के अनुसार 20.3 प्रतिशत शेयर के साथ सरकारी (सॉवरिन) विदेशी ऋण 95.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था जबकि गैर-सरकारी विदेशी ऋण 376.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था।

6.37 पिछले कई वर्षों में, भारत के विदेशी ऋण के स्टॉक की संरचना में ढांचागत परिवर्तन हुआ है। कुल विदेशी ऋण में रियायती ऋण का अनुपात वर्ष 1991-2000 के दौरान औसत 42.9 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2011-2015 के दौरान 11.7 प्रतिशत रह गया है और यह मार्च, 2017 के अंत में 9.3 प्रतिशत

रह गया है। कुल विदेशी ऋण में गैर-सरकारी ऋण का शेयर वर्ष 1990 में 45.3 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2000 के दशक में 65.6 प्रतिशत हो गया तथा मार्च, 2017 के अंत की स्थिति के अनुसार, 79.7 प्रतिशत शेयर के साथ पिछले 5 वर्षों में 80.1 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि पर है।

6.38 मार्च, 2016 में समाप्त अवधि की तुलना में मार्च, 2017 में समाप्त अवधि में विदेशी ऋण के अधिकांश संकेतकों (सारणी 11) में सुधार हुआ है, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है।

- पिछले वर्ष में हुई 2.2 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में बकाया विदेशी ऋण 2.7 प्रतिशत (13.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर) कम हुआ। भारतीय रुपए की तुलना में यूएस डॉलर के मूल्यहास के परिणामस्वरूप मूल्य हानि 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की थी। विदेशी ऋण में मूल्य प्रभाव को छोड़कर, विदेशी ऋण में गिरावट 13.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की

- बजाय 14.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाती।
- जीडीपी की तुलना में विदेशी ऋण का अनुपात 23.5 प्रतिशत से गिरकर 20.2 प्रतिशत रह गया।
  - ऋण चुकाने से संबंधित अनुपात 8.8 प्रतिशत से घटकर 8.3 प्रतिशत रह गया।
  - कुल ऋण की तुलना में विदेशी मुद्रा भंडार का अनुपात 74.3 प्रतिशत से बढ़कर 78.4 प्रतिशत हो गया।
  - कुल विदेशी ऋण में रियायती ऋण का अनुपात 9.0 प्रतिशत से बढ़कर 9.3 प्रतिशत हो गया।
  - कुल विदेशी ऋण में अल्पकालिक ऋण (अवशिष्ट परिपक्वता) का हिस्सा 42.7 प्रतिशत से गिरकर 41.5 प्रतिशत रह गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अल्पावधिक ऋण (मूल परिपक्वता) में हुई वृद्धि एफसीएनआर (बी) जमा राशियों में हुई गिरावट,

जो उनके मोचन को परिलक्षित करती है, से उत्पन्न प्रति संतुलन से अधिक थी।

- विदेशी मुद्रा भंडार की तुलना में अल्पावधिक ऋण (अवशिष्ट परिपक्वता) भी 57.4 प्रतिशत से घटकर 52.9 प्रतिशत रह गया।
- विदेशी मुद्रा भंडार की तुलना में केवल अल्पावधिक ऋण (मूल परिपक्वता) 23.1 प्रतिशत से मामूली वृद्धि दर्शाते हुए 23.8 प्रतिशत हो गया और कुल विदेशी ऋण की तुलना में अल्पावधिक ऋण (मूल परिपक्वता) व्यापार संबंधी क्रेडिटों में हुई वृद्धि के कारण 17.2 प्रतिशत से मामूली वृद्धि दर्शाते हुए 18.6 हो गया।

6.39 धारणीयता, नकदी और ऋण चुकाने की क्षमता पर जोर देने वाली भारत की विवेकपूर्ण विदेशी ऋण प्रबंध नीतियों ने विदेशी ऋण की मात्रा को बढ़ने से रोक कर सामान्य स्तर पर रखा है। विदेशी ऋण की

### सारणी 11. भारत के प्रमुख विदेशी ऋण सूचक (प्रतिशत)

वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 सं <sup>०</sup>	2016-17 अ <sup>०</sup>
विदेशी ऋण (बिलियन अमेरिकी डॉलर)	409.4	446.2	474.7	485.0	471.9
विदेशी ऋण में वृद्धि (%)	13.5	9.0	6.4	2.2	-(2.7)
जीडीपी की तुलना में कुल विदेशी ऋण	22.4	23.9	23.9	23.5	20.2
ऋण चुकाने का अनुपात	5.9	5.9	7.6	8.8	8.3
कुल विदेशी ऋण की तुलना में रियायती ऋण	11.1	10.4	8.8	9.0	9.3
कुल विदेशी ऋण की तुलना में विदेशी मुद्रा भंडार	71.3	68.2	72.0	74.3	78.4
विदेशी मुद्रा भंडार की तुलना में अल्पावधिक विदेशी ऋण <sup>१</sup>	33.1	30.1	25.0	23.1	23.8
कुल ऋण की तुलना में अल्पावधिक विदेशी ऋण <sup>१</sup>	23.6	20.5	18.0	17.2	18.6
कुल ऋण की तुलना में अल्पावधिक ऋण (अवशिष्ट परिपक्वता)	42.1	39.7	38.5	42.7	41.5
विदेशी मुद्रा भंडार की तुलना में अल्पावधिक ऋण (अवशिष्ट परिपक्वता)	59.0	58.2	53.5	57.4	52.9

स्रोत: आरबीआई

टिप्पणी: सं<sup>०</sup> संशोधित; अ<sup>०</sup> अनंतिम, <sup>१</sup> अल्पावधिक ऋण मूल परिपक्वता पर आधारित है।

ऋण चुकाने का अनुपात चालू खाता रसीदों (आफिशियल अंतरणों का निवल) के संबंध में सकल ऋण चुकाने से संबंधित भुगतान का अनुपात है।

संरचना सही ढंग से अनुरक्षित तुलनात्मक रूप से लंबी परिपक्वता प्रोफाइल को दर्शाती है और जहां तक स्रोतों का संबंध है, यह मोटे तौर पर संतुलित है।

### अंतरराष्ट्रीय तुलना

6.40 विदेशी ऋण की अंतरराष्ट्रीय तुलना से यह ज्ञात होता है कि भारत अब भी कम कमजोर देशों में शुमार है। भारत के प्रमुख ऋण अन्य विकासशील ऋणी देशों की तुलना में बेहतर हैं। शीर्ष स्थान पर रहने वाले 10 विकासशील ऋणी देशों में सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) की तुलना में भारत का 23.4 प्रतिशत विदेशी ऋण स्टॉक सबसे कम पांचवें क्रम पर है और विदेशी ऋण के संबंध में विदेशी मुद्रा भंडार द्वारा प्रदत्त सुरक्षा के संबंध में वर्ष 2015 में 69.7 प्रतिशत के साथ भारत का स्थान सबसे ऊपर वालों में छठे क्रम पर था (सारणी 12)।

6.41 विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा संयुक्त रूप से विकसित तिमाही विदेशी ऋण सांख्यिकी डाटाबेस के आधार पर विकासशील राष्ट्रों में हालांकि भारत तीसरा बड़ा ऋणी देश है, फिर भी कुल विदेशी ऋण की तुलना में अल्पकालिक ऋण का शेर वर्ष 2016 की तीसरी तिमाही सितंबर के अंत में और वर्ष

2016 की चौथी तिमाही (दिसंबर को समाप्त) में केवल क्रमशः 16.8 प्रतिशत और 18.8 प्रतिशत रहा है, जबकि इसी अवधि में शीर्षस्थ ऋणी देश चीन का ऋण क्रमशः 56.7 प्रतिशत और 56.4 प्रतिशत रहा है। विश्व में सबसे अधिक ऋणी देशों में यू.एस. दिसंबर 2016 को समाप्त अवधि की स्थिति के अनुसार शीर्षस्थ ऋणी देश है, उसके बाद यू.के., फ्रांस और जर्मनी का स्थान है। चीन 13वें स्थान पर है जबकि भारत दूर के 24वें स्थान पर है।

### निष्कर्ष

6.42 वर्ष 2017 और 2018 में विश्व व्यापार में क्रमशः 3.8 प्रतिशत और 3.9 प्रतिशत की वृद्धि के अनुमान होने के चलते, व्यापार क्षितिज में नई रोशनी दिखाई देने लगी है। भारत का निर्यात मई, 2017 में लगातार 4 महीनों से सकारात्मक परिधि में बना हुआ है और अप्रैल-मई, 2017 में यह द्विअंकीय रहा है तथा वैदेशिक क्षेत्र के सभी संकेतक जैसे कि आयात के लिए आरक्षित मुद्रा कवर, जीडीपी में विदेशी ऋण के अनुपात, विदेशी ऋण के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का कवर और ऋण शोधन अनुपात सकारात्मक स्थिति में हैं। तथापि, घरेलू क्षेत्र में बढ़ते व्यापार घाटे और वैश्विक स्तर पर

सारणी 12. शीर्षस्थ दस विकासशील ऋणी देशों की अंतरराष्ट्रीय तुलना, 2015

क्रम सं०	देश	सकल राष्ट्रीय आय की तुलना में विदेशी ऋण स्टॉक (प्रतिशत)	ऋण सेवा अनुपात (प्रतिशत)	कुल ऋण की तुलना में विदेशी मुद्रा भंडार (प्रतिशत)	कुल विदेशी ऋण स्टॉक (मि. अमरीकी डॉलर)
1	चीन	13.1	4.7	235.9	1,418,291
2	बंगलादेश	18.6	4.1	69.9	38,640
3	फिलीपींस	22.0	9.9	95.2	77,725
4	पाकिस्तान	22.9	12.9	27.2	65,482
5	भारत	23.4	10.9	69.7	479,559
6	ब्राजील	31.3	38.1	65.2	543,399
7	थाईलैंड	35.2	6.9	116.7	129,654
8	पेरू	35.6	11.5	91.6	65,938
9	इंडोनेशिया	37.0	32.1	33.5	308,540
10	मेक्सिको	37.5	13.2	40.7	426,334

स्रोत: विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय ऋण सांख्यिकी, 2017

टिप्पणी: जीएनआई की तुलना में विदेशी ऋण स्टॉक के अनुपात के आधार पर देशों को क्रमबद्ध किया गया है।

उभर रहे संरक्षणवादी रुझान पर अल्पावधिक संदर्भ में नजर रखनी चाहिए। इस बीच भारत को विश्व निर्यात के कम से कम 5 प्रतिशत हिस्से के सम्मानजनक स्तर तक पहुंचने के लिए सुविचारित रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है जो इस समय वर्ष 2011 से 2016 तक 1.7 प्रतिशत पर स्थिर रहा है और कभी-कभी गिरकर 1.6 प्रतिशत स्तर तक भी पहुंच जाता है।

### संदर्भ

1. OECD (2017), Secretary General Angel Gurría in his speech on the occasion of The Bill Frenzel champion of Free Trade Award-Economic Club of Minnesota, 19 April 2017. <http://www.oecd.org/trade/facing-the-facts-about-trade.htm>
2. OECD (2017a) "Fixing Globalization: Time to Make it Work for All" Better Policies Series (April 2017).
3. OECD (2017b), "International Trade: Free, Fair and Open", TAD/TC/RD(2017)4, April 2017.
4. OECD (2017c): on "Integration versus Isolation: Strengthening Communications on the impacts of Trade" Power point presentation of Mr. Bruce Stokes, Director Global Economic Attitudes of PEW Research Centre in the Trade Communications Conference, 25-26 April 2017, Paris.
5. WTO OMC (2017): "Report on G-20 Trade Measures", 30 June 2017.